● वर्ष : 17 ● अंक : 143 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS
RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928
www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित शनिवार 14 मार्च 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

कांग्रेस ने बोडोलैंड के साथ विश्वासघात किया भाजपा ने दिलाई स्थायी शांतिः प्रधानमंत्री

एजेंसी। गुवाहाटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को असम के कोकराझार में आयोजित रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बोडोलैंड के साथ वर्षों तक विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों तक बोडोलैंड क्षेत्र कांग्रेस के झूठे वादों और कागजी समझौतों का साक्षी रहा, जबकि भाजपा-राजग सरकार ने क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के कारण वे कोकराझार नहीं पहुंच सके और गुवाहाटी से ही लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से क्षमा मांगते हुए कहा कि वे दिल्ली से कोकराझार आने के लिए निकले थे, लेकिन मौसम की वजह से गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा। मोदी ने कहा कि जब जनता ने केंद्र और असम दोनों जगहों से कांग्रेस को हटाकर भाजपा-राजग को मौका दिया, तब सरकार ने बोडोलैंड में स्थायी शांति के लिए ठोस प्रयास शुरू किए। इसी सोच के साथ वर्ष 2020 में बोडो शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पहली बार सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक मंच पर लाया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोकराझार और आसपास के क्षेत्रों ने बीते दशकों में हिंसा और अशांति का कठिन दौर देखा है, जब यहां की पहाड़ियों में बम और गोलियों की आवाज गूंजती थी लेकिन आज स्थिति बदल रही है और क्षेत्र में शांति तथा विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा-राजग की "डबल इंजन" सरकार असम की विरासत के संरक्षण और तेज विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कोकराझार में 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इनमें से 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बोडोलैंड क्षेत्र की सड़कों के विकास पर खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 के समझौते के तहत किए गए वादों को लगातार पूरा किया जा रहा है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बातचीत, भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर जोर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, बढ़ते संघर्ष और उसके संभावित वैश्विक प्रभावों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा, नागरिकों की मौत और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को लेकर भारत गहरी चिंता व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान यह भी रेखांकित किया कि सामान और ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही भारत के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि यदि ऊर्जा आपूर्ति या व्यापारिक

मार्गों में किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर न केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा संकट का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने तनाव कम करने और रचनात्मक बातचीत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि हालात और ज्यादा खराब न हों। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट परियोजना भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार और संपर्क का एक अहम रणनीतिक मार्ग मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार मार्गों और प्रवासी समुदायों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। भारत इन परिस्थितियों में संतुलित कूटनीति के जरिए अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय शांति, दोनों को साधने की कोशिश कर रहा है। भारत लगातार क्षेत्र में शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता रहा है। यह अहम भी है क्योंकि पश्चिम एशिया में अस्थिरता का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रह रहे बड़े भारतीय समुदाय पर सीधे तौर पर पड़ सकता है।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

गैस संकटः सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत?

देश के कई हिस्सों में रसोई गैस को लेकर जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, उसने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के पास ना तो रसोई गैस है ना केरोसिन तेल है और ना ही लकड़ी उपलब्ध हो रही है। कई स्थानों पर तो बिजली सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में घर में खाना बनाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। एक ओर सरकार दावा कर रही है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। देश के सैकड़ो स्थान से इस बात के वीडियो और फोटो समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में प्रदर्शित हो रहे हैं। कई स्थानों पर डीलर खुले तौर पर कह रहे हैं, उनके पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है। पिछले कई दिनों से गैस की बुकिंग और सप्लाई बंद है। यह विरोधाभास केवल प्रशासनिक, नीतिगत और व्यवस्था की समस्या नहीं है वरन उन करोड़ों लोगों की समस्या है जिनके घर पर ना तो चाय बन पा रही है ना खाना बन पा रहा है।

जो सरकार के दावों की हकीकत को उजागर कर रहा है। भारत में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों—इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा निजी गैस कंपनियां भी गैस सप्लाई करती हैं लेकिन सभी कंपनियों की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। सरकार का तर्क है, इन कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार है। वितरण प्रणाली सामान्य रूप से चल रही है, पर वास्तविकता में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे है। 1800 से 2000 रुपए में एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर कालाबाजारी से मिल रहा है। वही कमर्शियल गैस सिलेंडर 4000 रुपये तक में बिक रहा है। सरकार इसे वितरण तंत्र की गंभीर खामी बताकर पल्ला झाड़ रही है।

जमीनी स्तर पर डीलरों का कहना है, उन्हें कंपनियों से समय पर पर्याप्त संख्या में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। पोर्टल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। गैस डीलर भी जिस माध्यम से बुकिंग करते हैं उसका भी पोर्टल बार-बार या तो धीमा हो जाता है या बंद हो जाता है। जिसके कारण वह उपभोक्ताओं की मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को कई दिनों तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। जिसके कारण करोड़ों घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। इससे सवाल उठता है, यदि उत्पादन और भंडारण पर्याप्त है, तो फिर गैस की आपूर्ति में बाधा क्यों है? इस समस्या से आम आदमी से लेकर होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों और शादी ब्याह के आयोजनों में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

भारत-ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत, क्षेत्रीय हालात पर चर्चा

नई दिल्ली/तेहरान। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका-इज़राइल के साथ बढ़ते तनाव के बाद क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हालात पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शुक्रवार को एक्स पर इसकी संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ ब्रिक्स से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि विदेश मंत्री अराघची ने अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए कथित आक्रामक कदमों तथा उनके क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी दी। अराघची ने कहा कि ईरान की सरकार, जनता और सशस्त्र बल हमलों के खिलाफ अपने वैध आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की निंदा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने बहुपक्षीय सहयोग के मंच के रूप में ब्रिक्स के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इस मंच को क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता एवं सुरक्षा के समर्थन में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

भारत के लिए बड़ी राहत, राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंध अस्थाई तौर पर हटाए

वॉशिंगटन। ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसमान छूती तेल की कीमतों

को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने एक चौंकाने वाला और रणनीतिक फैसला लिया है। अमेरिका ने गुरुवार को समुद्र में फंसे हुए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने की घोषणा की है। यह कदम वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ाने और 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी कीमतों को नीचे लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा जारी नए जनरल लाइसेंस के तहत यह छूट केवल 11 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, यह अनुमति केवल उसी रूसी तेल के लिए दी गई है जो 12 मार्च की मध्यरात्रि से पहले जहाजों पर लोड किया जा चुका था और वर्तमान में समुद्र में ट्रांजिट में है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट के अनुसार, इस निर्णय से बाजार में करोड़ों बैरल कच्चा तेल तत्काल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे ईरान संकट के कारण उत्पन्न हुई तेल की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी।वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक अल्पकालिक उपाय है और इससे रूसी सरकार को कोई दीर्घकालिक या सार्थक वित्तीय लाभ नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाना और अमेरिकी उपभोक्ताओं के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना है।

हापुड़ में नेता के घर से 55 एलपीजी सिलेंडर बरामद, गैस संकट के बीच जमाखोरी का भंडाफोड़

हापुड़। जिले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध जमाखोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। एक तरफ जहां आम जनता वैश्विक तनाव और आपूर्ति में बाधा के कारण रसोई गैस के एक-एक सिलेंडर के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों को छिपाकर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हापुड़ प्रशासन की टीम ने स्थानीय नेता अब्दुल रेहान के आवास पर छापेमारी कर वहां से 55 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब पूरे क्षेत्र में गैस की भारी किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गैस संकट का फायदा

उठाकर सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर रहे हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इसी क्रम में जब अधिकारियों को अब्दुल रेहान के घर पर बड़ी संख्या में सिलेंडर जमा होने की सटीक जानकारी मिली, तो संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम ने वहां छापेमारी की। घर के भीतर और स्टोर रूम में सिलेंडरों का बड़ा जखीरा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। प्रशासन ने तत्काल सभी 55 सिलेंडरों को जब्त कर लिया और उन्हें सुरक्षित रूप से संबंधित विभाग को सौंप दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों के चक्कर काटने और कई दिनों के इंतजार के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि प्रभावशाली लोग अपने घरों में सिलेंडरों का अंबार लगाए बैठे हैं।

संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरंभ

एजेंसी। समालखा(हरियाणा)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का शुक्रवार को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने उद्घाटन किया। इस दौरान सरकार्यवाह की ओर से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संघ ने बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अपने यहां हिंदुओं के अधिकारों का संरक्षण करे। तीन दिवसीय यह बैठक हरियाणा के समालखा स्थित माधव सृष्टि परिसर में आयोजित की गई है। प्रतिनिधि सभा के प्रारंभ के बाद यहां सह सरकार्यवाह सीआर मुकुंद ने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर एवं प्रदीप जोशी सहित अन्य

बांग्लादेश सरकार से की हिंदुओं के संरक्षण की मांग

पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के शुरुआती सत्रों में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से आए सुधार और मणिपुर में संघ के प्रयासों से आए सकारात्मक परिणामों का स्वागत किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया गया कि हिंदुओं के अधिकारों का वहां संरक्षण प्रदान करे। सीआर मुकुंद ने बताया कि सरकार्यवाह ने अपने प्रतिवेदन में यह जानकारी दी कि संघ के शताब्दी वर्ष में किए गए प्रयासों से 4 हजार स्थान पर 5 हजार से अधिक शाखाओं में वृद्धि हुई है। गृह संपर्क अभियान के तहत संघ के कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे हैं। तीन लाख से अधिक गांव में संघ के कार्यकर्ता गए हैं। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां संघ के कार्यकर्ता साम्यवादी विचारधारा, मुसलमानों और ईसाई परिवारों से भी मिले हैं। अकेले केरल में 55 हजार से अधिक मुस्लिम और 54 हजार से अधिक ईसाई परिवारों में संघ के कार्यकर्ता संघ और समाज से जुड़े विषय लेकर गए हैं। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के नाते 36 हजार से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इसमें अरुणाचल के एक दुर्गम क्षेत्र में आयोजित हिंदू सम्मेलन का उदाहरण उल्लेखनीय है। संघ के शताब्दी वर्ष में दो प्रकार के कार्यक्रमों की योजना की गई जिनमें एक संगठन विस्तार और दूसरा समाज की सज्जन शक्ति को सद्भाव, समरसता के लिए संगठित करने का उद्देश्य रखा गया। मुकुंद ने बताया कि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत पिछले वर्ष दो अक्टूबर को नागपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत के सान्निध्य में हुई।

प्राकृतिक आपदा प्रभावित 6 राज्यों को 1,912 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान 'मोंथा' से प्रभावित छह राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस राशि में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़, गुजरात को 778.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़, नगालैंड को 158.41 करोड़ और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के शुरुआती बैलेंस के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन होगी। सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर संभव मदद प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

सोनिया गांधी से जुड़े मामले में सुनवाई टली, अब मामले की 30 मार्च को सुनवाई

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित जालसाजी को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन मामले में दायर रिवीजन पिटीशन पर शुक्रवार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली ये सुनवाई टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की गई थी। इसके बाद अदालत ने नई तारीख दी। ये याचिका वकील विकास त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सितंबर में खारिज

किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी फैसले को त्रिपाठी ने चुनौती दी है। दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका में नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी। आरोप है कि नागरिकता मिलने से 3 साल पहले, यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में शामिल था। इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब सोनिया गांधी के पास 1983 तक नागरिकता नहीं थी, तब 1980 में किस आधार पर और किन दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया?

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया, एक और महत्वपूर्ण समझौता करने की कगार पर भारत-अमेरिका

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों पर जोर देकर कहा कि आज की दुनिया में दोनों देशों की दोस्ती बहुत जरूरी है। अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत तालमेल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। गोर ने महज दो महीने पहले अमेरिकी दूत के रूप में कार्यभार संभाला है, शुरुआत में ही साफ किया कि मोदी और ट्रंप ही वे दो एकमात्र डीलमेकर थे, जिन्होंने इस व्यापार समझौते को सफलता की

दहलीज तक पहुंचाया। सर्जियो ने कहा कि ट्रंप के प्रशासन के दौरान भारत-यूएस संबंध और मजबूत हुए हैं, ट्रेड डील पर बात कर उन्होंने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पार्टनर बताया। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत गोर ने महत्वपूर्ण घोषणा की, उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं। यह प्रगति दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के ढांचे पर बनी सहमति के ठीक कुछ दिनों बाद देखने को मिली है। बात दें कि गोर इस समय भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। इसके पहले गोर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के सहायक और डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनेल के पद पर थे। उनके नेतृत्व में पूरे संघीय सरकार में हजारों राजनीतिक नियुक्तियां रिकॉर्ड समय में की गईं। व्हाइट हाउस से पहले, गोर ने ट्रंप जूनियर के साथ मिलकर विनिंग टीम पब्लिशिंग की स्थापना की थी। यह अमेरिका के प्रमुख कंजरवेटिव प्रकाशन संस्थानों में से एक है।

रक्तदान से ट्रांसजेंडर और उच्च जोखिम वाले समूहों को बाहर रखने के फैसले पर केंद्र अडिग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिक पुरुषों और महिला सेक्स वर्कर्स को संभावित रक्तदाताओं की सूची से बाहर रखने के अपने निर्णय का पुरजोर बचाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसी समुदाय के प्रति भेदभाव की भावना से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों के आधार पर उठाया गया है। सरकार के अनुसार, इन विशिष्ट समूहों में एचआईवी और अन्य संक्रामक रोगों का प्रसार आम आबादी की तुलना में कहीं अधिक पाया गया है, जो रक्तदान की सुरक्षा प्रक्रिया के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया

कि राष्ट्रीय रक्त नीति का प्राथमिक लक्ष्य सबसे सुरक्षित डोनर पूल से रक्त प्राप्त करना है। उन्होंने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि इन समूहों में संक्रमण का खतरा सामान्य लोगों के मुकाबले 6 से 13 गुना तक अधिक होता है। ऐसी स्थिति में, उच्च जोखिम वाले समूहों से रक्त या उसके घटक प्राप्त करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और महिला सेक्स वर्कर्स में एचआईवी के अलावा हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी जैसे गंभीर संक्रमणों की दर भी काफी ऊंची है। मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि इस तरह के प्रतिबंध केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई विकसित और यूरोपीय देशों में भी यौन रूप से सक्रिय समलैंगिक पुरुषों और उच्च जोखिम वाले समूहों को रक्तदान से स्थायी रूप से वर्जित रखने के कड़े वैश्विक मानक लागू हैं। सरकार ने अदालत में इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत अधिकारों या समानता के दावों तक सीमित नहीं है।

नवजात शिशु की मौत मामले में झारखंड के अधिकारियों को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के मामले में अस्पताल कर्मियों की तरफ से की गई लापरवाही का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस न दिए जाने के बाद पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रख कर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा। खबरों के मुताबिक, अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को शिशु के शव को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए मजबूर किया और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

श्रमिकों की मौत के मामले में हरियाणा सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बिलासपुर क्षेत्र के पास एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से सात श्रमिकों की मौत और तीन अन्य के घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने बताया कि 10 मार्च 2026 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 9 मार्च को हरियाणा के गुरुग्राम के बिलासपुर क्षेत्र के पास एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से कम से कम सात श्रमिकों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। कम से कम 10 श्रमिकों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। यह घटना उस स्थल पर हुई जहां एक आगामी आवासीय परियोजना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा दल, बचावकर्मी, दमकलकर्मी और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों सहित अन्य एजेंसियां मलबे के नीचे फंसे श्रमिकों की तलाश कर रही थीं। आयोग ने रिपोर्ट में घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति और मृतक आश्रितों एवं घायल व्यक्तियों के परिजनों को दिए गए मुआवजे का भी विवरण मांगा है।

मानवाधिकार आयोग का लापता व्यक्तियों और मानव तस्करी को लेकर पांच राज्यों को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और उन्हें ढूंढने में प्रशासन के निराशाजनक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बताया कि 9 मार्च 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि मानव तस्करी के अधिकतम मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। किशोर की तस्करी के मामलों में ओडिशा सबसे आगे है। उसके बाद बिहार है। किशोरियों की तस्करी के मामलों में राजस्थान में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह संदेह है कि इन बच्चों को भीख मांगने, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेला जाता है। बिहार में 2013 से हर साल दर्ज होने वाले 12-14 हजार गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में से दो-तिहाई को ही बचाया जा सका है। इनमें से कई बच्चे हैं। आयोग ने रिपोर्ट में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों और एनसीआरबी से इन राज्यों में लापता व्यक्तियों की स्थिति पर नवीनतम सांख्यिकीय आंकड़े भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर की कानूनी व्याख्या को विस्तार देकर इसे अधिक समावेशी बनाने का है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में आज संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक मौजूदा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को संशोधित करेगा। उल्लेखनीय है कि 2019 अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए अक्टूबर 2025 में न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

मणिपुरी महिला पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएचआरसी का नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। मणिपुर की एक महिला पर दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लड़कों के एक समूह की ओर से कथित हमले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8 मार्च को यह घटना तब घटी जब पीड़िता (मणिपुर की एक महिला) इलाके के एक पार्क में अपनी दोस्त के साथ तस्वीरें ले रही थी। उसी दौरान दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लड़कों के एक समूह ने पीड़िता पर अश्लील और नस्लीय टिप्पणी की जिसका उन्होंने विरोध किया लेकिन लड़कों के समूह ने उस महिला पर शारीरिक हमला कर दिया। आयोग ने रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और जांच की प्रगति का विवरण भी शामिल करने को कहा है।

डेटा संरक्षण कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली नई याचिका पर केंद्र को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने डाटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को भी दूसरे लंबित याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया है। नई याचिका अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने दायर की है। याचिका में डाटा प्रोटेक्शन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके पहले 16 फरवरी को भी कोर्ट ने डाटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि ये मामला संवेदनशील है। हमें दो कानूनों में संतुलन बनाना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं वेंकटेश नायक, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और पत्रकार नितिन सेठी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि नया डाटा प्रोटेक्शन कानून सूचना के अधिकार कानून को गंभीर रूप से कमजोर करती है और केंद्र को इस मामले में असीमित शक्तियां देती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि ये कानून निजता की रक्षा करने में पूरे तरीके से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि छेनी का इस्तेमाल करने के बजाय हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है।

तिरुपति प्रसादम में मिलावट के कथित दुष्प्रचार को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति प्रसादम में मिलावट को लेकर कथित दुष्प्रचार रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। कोर्ट ने कहा कि अपनी शिकायत उचित फोरम पर रखिए। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की जांच में जो भी सामने आएगा वो संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा। याचिका में मांग की गई थी कि आंध्र प्रदेश सरकार को इस बात का निर्देश दिया जाए कि कुछ लोग और कुछ संगठन होर्डिंग्स, पोस्टर्स और सार्वजनिक बयान के जरिये दुष्प्रचार फैला रहे हैं। कोर्ट ने तिरुपति प्रसादम में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए 4 अक्टूबर, 2024 को एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) डायरेक्टर को विशेष जांच दल (एसआईटी) की टीम की मानिटरिंग करने का निर्देश दिया था।

यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए मिशन मोड पर काम जारीः रेखा गुप्ता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए ड्रेन की सफाई का काम मिशन मोड में चल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर बडुसराय पुल और पंखा रोड ड्रेन में नई अम्फीबियस मशीनें तैनात की हैं। उन्होंने कहा कि इन मशीनों से ड्रेनों की डी-सिल्टिंग, कचरा हटाने और जलकुंभी की सफाई का काम तेजी और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। इससे पानी की निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और बरसात में जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर दिल्ली जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है और दिल्ली के कुल नालों से निकलने वाली लगभग 75 प्रतिशत सिल्ट इसी ड्रेन के माध्यम से आती है। उन्होंने कहा कि वर्षों से जमा हुई भारी मात्रा में सिल्ट को निकालना पहले बेहद कठिन कार्य माना जाता था लेकिन अब इन आधुनिक फ्लोटिंग मशीनों के माध्यम से यह संभव हो पा रहा है। ये मशीनें ड्रेन के बीचोंबीच जाकर सिल्ट को निकाल सकती हैं, जिससे लंबे समय से जमा गाद को हटाने की प्रक्रिया तेज होगी। उन्होंने बताया कि अनुमान के मुताबिक नजफगढ़ ड्रेन में करीब एक करोड़ मीट्रिक टन से अधिक सिल्ट जमा है। इसे हटाने के लिए इन आधुनिक अम्फीबियस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने और अम्फीबियस मशीनें खरीदने का भी निर्णय किया है। इनमें से एक मशीन पहले ही लाई जा चुकी थी, जबकि आज चार नई मशीनों का जलावतरण किया गया। बाकी मशीनें जल्द ही विभाग को सौंप दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब केवल मॉनसून से पहले ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष नालों की डी-सिल्टिंग का कार्य कर रही है ताकि बारिश के समय जलभराव की समस्या को प्रभावी रूप से रोका जा सके। मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार यमुना और उनसे जुड़ी बड़ी ड्रेनों की सफाई के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आधुनिक मशीनों का उपयोग कर रही है ताकि यमुना को अविरल और निर्मल बनाया जा सके। साथ ही दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और जलभराव से मुक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि नजफगढ़ ड्रेन और उससे जुड़ी प्रमुख ड्रेनों की सफाई के लिए अत्याधुनिक अम्फीबियस मशीनों का उपयोग दिल्ली सरकार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इन आधुनिक मशीनों की मदद से वर्षों से जमा सिल्ट, कचरा और जलकुंभी को प्रभावी ढंग से हटाया जा सकेगा, जिससे ड्रेनों की जल प्रवाह क्षमता बढ़ेगी और बरसात के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया एक प्रमुख वादा पंखा रोड का सौंदर्यकरण, उसे स्वच्छ और कूड़ा-मुक्त बनाना तथा पंखा रोड ड्रेन की वर्षों से लंबित सफाई कराना था। लंबे समय से इस ड्रेन की सफाई नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में स्थानीय निवासियों को जलभराव और दुर्गंध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सरकार बनने के बाद से ही इस वादे को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। ड्रेन की नई दीवारों का निर्माण कराया गया है और पहले 100 दिनों के भीतर ड्रेन की प्रारंभिक सफाई और एक हिस्से का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा किया गया।

एम्फीबियस एक्सकेवेटर मशीनों की विशेषताएं:सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से ये मशीनें बडुसराय पुल, काकरोला, द्वारका, उत्तम नगर समेत कई स्थानों पर तैनात की गई हैं। सरकार का लक्ष्य इन मशीनों से साल भर ड्रेनों की डी-सिल्टिंग जारी रहे, ताकि मानसून में जलभराव की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। शॉर्ट बूम एम्फीबियस मशीन की लागत लगभग 1.27 करोड़ रुपये है। इसमें करीब 6 मीटर लंबा बूम, 0.20 घन मीटर बकेट क्षमता और 65 एचपी इंजन है। यह मशीन 5 मीटर चौड़े संकरे ड्रेन में भी चल सकती है और ड्रेन के अंदर ही काम करने में सक्षम है। इसमें 2.25 घन मीटर क्षमता का कचरा बिन होता है। यह मशीन सूखी, दलदली और पानी भरी परिस्थितियों में काम करते हुए सिल्ट, कचरा, मलबा, स्लज और जलकुंभी जैसी तैरती सामग्री हटाने में सक्षम है। लॉन्ग बूम एम्फीबियस मशीन की लागत लगभग 3.15 करोड़ रुपये है। इसमें करीब 15 मीटर लंबा बूम, 0.50 घनमीटर बकेट क्षमता और 135 एचपी इंजन है। यह मशीन करीब 9 मीटर गहराई तक काम कर सकती है और ड्रेन के अंदर तथा जमीन दोनों पर चल सकती है। यह भी सूखी, दलदली और जलमग्न परिस्थितियों में काम करते हुए सिल्ट, कचरा, मलबा और जलकुंभी हटाने में बेहद प्रभावी है।

मिशन रीकनेक्ट 3.0 – आपका फोन अपने घर की ओर

» पीएस लाहौरी गेट के स्टाफ द्वारा चोरी/गुम हुए 15 मोबाइल फोन पीड़ितों को सौंपे गए

लोकतंत्र की शान

सड़क अपराधों पर अंकुश लगाने और आम जनता को ठोस राहत प्रदान करने के उद्देश्य से "मिशन रीकनेक्ट 3.0 – आपका फोन अपने घर की ओर" के तहत एक समर्पित टीम का गठन किया गया। इस टीम में एएसआई कविंदर, एचसी नितेश राठी और एचसी अमित मलिक शामिल थे, जो इंस्पेक्टर योगेश्वर, एसएचओ/पीएस लाहौरी गेट के नेतृत्व और पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे थे। इस टीम ने उत्तर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल चोरी/गुम होने की घटनाओं से निपटने के लिए लक्षित अभियान और CEIR आधारित ट्रेसिंग को तेज किया। पुलिस टीम को इस अभियान में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई और कुल 20 उच्च मूल्य के चोरी/गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस सफलता का श्रेय सूक्ष्म तकनीकी निगरानी और एकत्रित की गई जमीनी खुफिया जानकारी को जाता है। दिनांक 05.03.2026 को पीएस लाहौरी गेट में एक रिस्टिट्यूशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसएचओ/लाहौरी गेट द्वारा 15 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। पीएस लाहौरी गेट के स्टाफ द्वारा किया गया यह सराहनीय कार्य दिल्ली पुलिस के पेशेवर दृष्टिकोण और "Service First" की भावना को दर्शाता है। यह पहल केवल कानून प्रवर्तन का प्रयास नहीं है, बल्कि पीड़ितों के हित में उठाया गया एक कदम है, जिसका उद्देश्य सेवा करना, सुरक्षा प्रदान करना और न्याय को उसके वास्तविक रूप में स्थापित करना है।

(राजा बंथिया) आईपीएस
उपायुक्त पुलिस
उत्तर जिला, दिल्ली

राहुल गांधी बोले- नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि अमेरिका के हितों के लिए काम कर रहे

लोकतंत्र की शान, जीशान अली

नई दिल्लीः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि अमेरिका के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जब वह यह बात संसद में कहने जा रहे थे तो प्रधानमंत्री भाग निकले, क्योंकि वह आंख से आंख नहीं मिला सकते। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार शाम को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दिग्गज नेता कांशीराम की जयंती के अवसर पर आयोजित संविधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांशीराम जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारत रत्न देने की मांग करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया गया। मोदी सरकार की विफल विदेश नीति पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में हैं और वही कर रहे हैं जो वह कह रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अडानी पर केस कर दिया है, जो वास्तव में भाजपा के खिलाफ मामला है, क्योंकि अडानी की कंपनी ही भाजपा का वित्तीय ढांचा है। इसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अमेरिका की बात नहीं मानी तो भाजपा की पूरी वित्तीय व्यवस्था का खुलासा कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम एपस्टीन फाइल्स में है और वे एपस्टीन के दोस्त रहे हैं। साथ ही, हरदीप पुरी की बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है। जब उन्होंने गुरुवार को यह बात संसद में उठानी चाही, तो स्पीकर ने उन्हें रोक दिया।

दिल्ली पुलिस पर हाई कोर्ट सख्त, कहा- जांच ही करते रहेंगे, तो आरोपों पर सुनवाई कब होगी?

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि वो आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान ने मकोका के मामले की जांच कब तक पूरी करेंगे। अगर कोई आरोपित दो साल से जेल में है, तो आप जांच में तेजी लाइए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान के वकील रेबेका जॉन ने कहा कि याचिकाकर्ता के आवाज के नमूने ले लिए गए हैं, लेकिन किसी दूसरे के आवाज के नमूने नहीं लिए गए। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोप तय हो गए हैं। अभी तक आरोप तय क्यों नहीं हुए। तब दिल्ली पुलिस के वकील अमित प्रसाद ने कहा कि अभी आगे की जांच जारी है। तब कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने अपराध किया है या नहीं ये ट्रायल से पता चलेगा, लेकिन आरोप तो तय होना चाहिए। 2024 में आरोपित को गिरफ्तार किया गया और अब 2026 आ गया। अगर दिल्ली पुलिस जांच ही करती रहेगी तो आरोप तय करने पर सुनवाई कैसे होगी। नरेश बाल्यान ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा हैकि उसके खिलाफ मकोका का मामला बनता ही नहीं है क्योंकि वो आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त नहीं रहा है। इसके पहले नरेश बाल्यान के वकील एन. हरिहरन ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मकोका चलाने के लिए पुख्ता साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि मकोका 15 एफआईआर के आधार पर किया गया है जो कपिल सांगवान और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए। उन्होंने कहा था कि नरेश बाल्यान का कपिल सांगवान और उसके गैंग से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून, 2025 को नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। नरेश बाल्यान ने इसके पहले भी उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत याचिका उच्च न्यायालय से वापस ले ली गई थी। उसके बाद बाल्यान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई, 2025 को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। उसके बाद बाल्यान ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर किया है। दरअसल, वसूली के मामले में 4 दिसंबर, 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर, 2024 की रात में गिरफ्तार किया था। इससे पहले भाजपा ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी किया था जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है। इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है। कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है। कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है। कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और भाजपानेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है। नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

फर्जी मेडिकल वीजा के सहारे रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े, निर्वासन की कार्रवाई शुरू

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। बाहरी जिले की विदेशी सेल (फॉरेनर सेल) ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोच लिया। पकड़े गए सभी लोग कथित तौर पर फर्जी मेडिकल वीजा के सहारे यहां रह रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ समन्वय कर निर्वासन की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। बाहरी जिले के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले की फॉरेनर सेल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में टीम को सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद इलाके में रह रहे हैं और बुल्गारिया के लिए मेडिकल वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। छह मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध लोग पीरागढ़ी चौक स्थित डीडीए पार्क के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर फॉरेनर सेल की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुप्त निगरानी शुरू की। पुलिस की मौजूदगी का आभास होते ही संदिग्ध इधर-उधर भागने लगे, लेकिन सतर्क टीम ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया। जांच के दौरान पकड़े गए लोगों की पहचान फारूक, एमडी सोजिब फकीर, सोहाग मिया, शहाबुद्दीन, एमडी शरजुल इस्लाम शाहिदुल, गोलाम रब्बानी, साजिब मिया, एमडी जाहिरुल, एमडी आलमगीर हुसैन और एमडी अब्दुल कुद्दूस के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान कोई भी वैध पहचान पत्र या यात्रा दस्तावेज नहीं दिखा सका। आगे की जांच में उनके पास मिले पासपोर्ट और वीजा भी समाप्त अवधि के पाए गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एफआरआरओ के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में इंस्पेक्टर सुंदर सिंह के नेतृत्व में एसआई अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल उमेद, रविंदर, अरुण, कांस्टेबल रोहित, सुमेर और महिला कांस्टेबल रेनू शामिल रहे। पूरी कार्रवाई एसीपी ऑपरेशंस वीरेंद्र दलाल के मार्गदर्शन में की गई। बाहरी जिले के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने को लेकर विपक्ष की तरफ से दोनों सदनों में दिया गया प्रस्ताव

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव 10 पन्नों का है जिसमें 7 कारण गिनाए गए हैं, जिनके आधार पर ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में दिए गए नोटिस में सदन के 130 सदस्यों और राज्यसभा में दिए गए नोटिस में 63 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। नियमों के कारण लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने शुक्रवार को मकर द्वार पर मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद में कानून के अनुसार नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूची से नाम हटाकर जनता को मताधिकार से वंचित किया है, जिसके लिए विपक्षी गठबंधन के साथ मिल कर यह कार्यवाही की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 324 (5) में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है।मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों को अध्यक्ष या चेयरमैन को नोटिस देना होता है। नोटिस स्वीकार होने पर इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। यदि समिति को आधार वैध लगते हैं तो प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई) से पारित होना आवश्यक है।

दिल्ली दंगा को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर संबंधी याचिका खारिज

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने ये आदेश दिया। इसके पहले एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को कपिल मिश्रा ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को निरस्त कर दिया था। इस बीच पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया का ट्रांसफर हो गया। अब ये मामला मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार के समक्ष चल रहा है। अश्विनी पंवार ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी है। अब इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य पेश किए जाएंगे। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि या तो जांच अधिकारी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं की या उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि आरोपित कपिल मिश्रा सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उसके बारे में ज्यादा जांच की जरुरत है। क्योंकि ऐसे लोग जनता के मत को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति से संविधान के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है। कपिल मिश्रा ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर करावल नगर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार के कानून मंत्री बनाये गए थे।

संक्षिप्त समाचार

अलविदा जुम्मा/चौथे जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण रूप से हुई संपन्न, पुलिस बल रहा मौजूद

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः रमजान मुबारक के चौथे जुमे/अलविदा जुम्मे को मस्जिदे नमाजियो से फुल हो गई। अमन शांति व भाईचारा के लिए दुआ भी कराई गई। तहसील क्षेत्र में रमजान मुबारक के चौथे जुमे को मस्जिदों में नमाज अदा कराई गई, गजरौला रोड, मोहल्ला कायस्थान, आखून चौक, नवाबान, काला शहीद, रहरा रोड, कुरेशियान, खंकर वाला कुआं, कनेटा रोड, लालबाग ऊंचा, संभल रोड, हिरन वाला आदि मोहल्लो में मौजूद मस्जिदों में रमजान मुबारक के चौथे जुमे/अलविदा जुम्मा की नमाज अदा कराई गई। इसके अलावा सिहाली जागीर, अगरौला कलां, मछरई, आगापुर, बावनखेड़ी, कालाखेड़ा, हैबतपुर बंजारा, गंगवार, शंकर गढ़ी, जयतोली, सूतावली, बासका कलां, बासका खुर्द, पीपलोती कलां, पीपलोती खुर्द, बुरावली, ढवारसी आदि गांवो की मस्जिदों में भी रमजान मुबारक के चौथे जुमे को नमाज को अदा कराया गया। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सुबह से ही जुमे की नमाज की तैयारिया की जा रही थी। नगर पालिका द्वारा मस्जिदों के आसपास छिड़काव व सफाई कर चूना आदि डलवाया गया था। जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती मेराज अहमद ने जुमे की नमाज को अदा कराया। इस मौके पर नगर की जामा मस्जिद सहित विभिन्न मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा तथा ड्रोन से निगरानी की गई।

जेबीएफ ने सरस्वती शिशु मंदिर में स्थापित कराई मुस्कान एडू लैब

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः गजरौला। जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन ने मुस्कान प्रोजक्ट के तहत सरस्वती शिशु मंदिर में 10 कंप्यूटर प्रदान किए हैं। मुस्कान एडू लैब में बच्चे अब तकनीकि शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे। शुक्रवार को इसका उद्घाटन कालरा एस्टेट के स्वामी अंशय कालरा एवं रोटरी क्लब आकर्षण हसनपुर के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।

बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्कूल के प्रबंधक कपिल कुमार सिंघल ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मौके पर जेबीएफ के चंदन प्रसाद, नवनीत सिंह, श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष डा. राजीव शुक्ला, नगर ब्राह्मण सभा के पंडित देवेंद्र शर्मा, रोहित शर्मा, डीपीआसी सतेंद्र शर्मा, संजीव सिंघल, सभासद ब्रजेश अग्रवाल, देवराज शर्मा, नितिन सिंघल, शलभ सिंघल, नीलाक्ष अग्रवाल, दिनेश चंद सिंघल, निगम वर्मा, पुष्पा अग्रवाल, ज्योति गोयल, दिया, हिना, हेमा प्रियंका, पूनम, प्रीती, ममता आदि मौजूद रहे।

AIMIM कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम ऑफिस पर सौपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुर। मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गैस सिलेंडरो की किल्लत दूर कर सुचारु रूप से होम डिलीवरी करवाये जाने की मांग की है। बता ते चले कि शुक्रवार को मजलिस के प्रदेश महामंत्री एवं हापुड़ बिजनौर के प्रभारी हाजी शहजाद खान एडवोकेट एवं हसनपुर विधानसभा प्रभारी छुनन्न अल्वी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम की गैर मौजूदगी में उनके कार्यालय में सौंपा गया,श्री खान ने कहा रमजान का महीना चल रहा है।

गैस की किल्लत के चलते उपभोक्ता परेशान है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के घरों तक गैस होम डिलीवरी कराई जाये। उन्होंने कहा कि आम जनता घरेलू गैस लेने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही है, रमजान ईद के मद्दे नजर खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में गैस की किल्लत ना होने दी जाये। उन्होंने कहा कि गैस की काला बाजारी ना होने दी जाये। हर गैस एजेंसी पर पुलिस बल को तैनात किया जाये। ताकि वहां पर भीड़ ना हो और जनता में भी अफ़वाह न फैल सके, हसनपुर विधानसभा प्रभारी छुनन्न अल्वी ने कहा कि बिजली की व्यवस्था ठीक प्रकार से कराई जाये। इस अवसर पर हाजी शहजाद खान, विधानसभा अध्यक्ष छुनन्न अल्वी, हाफिज आसिफ, शाहज़ेब सलमानी, आजम, मेहताब शेख, कादिर कुरैशी, निजाम नश्तर, कासिम एडवोकेट आदि मौजूद।

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक रविवार को

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हसनपुर की आवश्यक बैठक रविवार को नगर की ब्राह्मण धर्मशाला के सत्संग भवन में शाम 6 बजे से आयोजित की जाएगी, बैठक में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा जिसके लिए सभी सदस्यों से समय से पहुंचने की अपील की गई है, बता ते चले कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हसनपुर की मासिक बैठक महासभा के नगर अध्यक्ष पंडित विनय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी बैठक में संरक्षक मंडल एवं पदाधिकारी व सदस्य गणों से समय से पहुंचने की अपील की गई है, यह जानकारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हसनपुर के महामंत्री पंडित विवेक शर्मा द्वारा दी गई

बाबूराम जाटव बने अंबेडकर उद्यान समिति मोहल्ला खेवान हसनपुर के अध्यक्ष

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शुक्रवार को मोहल्ला खेवान हसनपुर में एक आवश्यक मीटिंग की गई जिसकी अध्यक्षता तीरथ प्रकाश उर्फ मलुआ नेताजी ने की व संचालन महेश जाटव ने किया, बैठक में अंबेडकर पार्क मोहल्ला खेवावन में चल रहे विवाद पर चर्चा की गई मलवा नेताजी ने विवाद के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और इस विवाद को समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने हेतु निर्णय लिए गए समाज के सम्मानित लोगों ने सर्वसम्मति से अंबेडकर उद्यान समिति के तत्वाधान में मनाए जाने वाले कार्यक्रम का अध्यक्ष बाबूराम जाटव को बनाया तथा अंबेडकर उद्यान समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष बाबूराम ने कहा की अंबेडकर उद्यान समिति पार्क पर शानदार और भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा समाज में अच्छे शिक्षा के माध्यम से तरक्की कर रहे मेधावी छात्रों को वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके युवाओं को भी सम्मानित किया जाएगा बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का काम अंबेडकर उद्यान समिति मोहल्ला खेवान करेगी, अंबेडकर उद्यान समिति मोहल्ला खेवान अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करेगी तथा हर स्तर पर हर वर्ग का सम्मान करेगी समिति प्राथमिकता के तौर पर सभी विवादों का निपटारा जल्द से जल्द करने में विश्वास करती है इस अवसर पर समिति का गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष बाबूराम जाटव को और महा सचिव बृजपाल सिंह, उपाध्यक्ष महेश जाटव को, महामंत्री दारा सिंह को, कोषाध्यक्ष चंद्र किरण को बनाया गया, और तीर्थ प्रकाश उर्फ मलवा नेताजी, हरपाल सिंह को संरक्षक बनाया गया, अवसर पर महेंद्र सिंह आर्य, सुशील भगत जी, रामपाल नेताजी, राजेंद्र गुड्डू, प्रकाश बारहमासी, फतेहचंद, राजवीर सिंह, करतार सिंह, राजीव भगत जी, विकास, नवल कुमार, सत्या, सुशील आदि सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जापान और सिंगापुर की सफल यात्रा के लिए मुख्यमंत्री योगी को दीं शुभकामनाएं

लोक तंत्र की शान

रायबरेली। राना बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति, रायबरेली के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को उनकी जापान एवं सिंगापुर की सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। समिति की वार्षिक पत्रिका "अवध केसरी" के दसवें अंक का भी मुख्यमंत्री योगी ने विधिवत विमोचन किया। भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जनपद रायबरेली के विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और महत्वपूर्ण प्रस्तावों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसमें जनपद में भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण तथा हैदरगढ़ स्थित शुगर मिल के बंद होने से किसानों को हो रही गन्ना उठान की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में जनपद रायबरेली के विकास एवं जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल होगी। मुख्यमंत्री ने जनहित में और भी बेहतर कार्य के लिए समिति के सदस्यों को प्रेरित किया।

संभल की शाही जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा, चौधरी मुशीर अली खान ने लोगों से गले मिलकर दी मुबारकबाद

लोक तंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल : संभल नगर की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में रमजान के पाक महीने के आखिरी जुम्मे यानी अलविदा जुम्मे की नमाज बड़े ही शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल में अदा की गई। नमाज में बड़ी संख्या में रोजेदारों और नमाजियों ने शिरकत की और देश में अमन-चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआएं मांगीं। नमाज के बाद मस्जिद परिसर में एक खूबसूरत भाईचारे का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर अलविदा जुम्मे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की चेयरमैन के पति चौधरी मुशीर अली खान भी मौजूद रहे। उन्होंने नमाजियों से मुलाकात की और सभी को अलविदा जुम्मे की दिली मुबारकबाद दी। चौधरी मुशीर अली खान ने कहा कि रमजान का महीना इंसान को सब्र, इंसानियत, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि हमें इस पाक महीने से मिली सीख को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए और समाज में आपसी मोहब्बत और एकता को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि समाज में अमन-चैन और भाईचारा बनाए रखें और एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होकर इंसानियत का संदेश फैलाएं। नमाज के बाद चौधरी मुशीर अली खान ने कई लोगों से गले मिलकर उन्हें अलविदा जुम्मे की मुबारकबाद दी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने उनके इस मिलनसार और सौहार्दपूर्ण व्यवहार की सराहना की। अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद परिसर और आसपास के इलाके में पूरी तरह शांति और अनुशासन का माहौल रहा। नमाज के बाद लोग अपने घरों को लौट गए और पूरे क्षेत्र में भाईचारे और सौहार्द की भावना देखने को मिली।

योगी सरकार ने लखनऊ को बनाया वर्ल्डक्लास सिटीः रक्षा मंत्री

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का शुक्रवार को लोकार्पण करते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास केवल कागज का विषय नहीं रह गया है बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन में दिख रहा है। इस परियोजना से लखनऊ के करीब 15 लाख लोगों को आवागमन में आसानी होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आईआईएम रोड से आउटर रिंग रोग तक 28 किमी के इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने में लगभग 7000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाते समय रास्ते में आने वाले डेढ़ सौ से ज्यादा वृक्षों को काटा नहीं गया बल्कि उन्हें दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया। यह अपने आप में पर्यारवण की रक्षा के लिए मिसाल है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना में सेना की जमीन का भी उपयोग हुआ है। इस परियोजना में सिविल और रक्षा क्षेत्र दोनों ने मिलकर काम किया है। जमीन आवंटन को लेकर कुछ चुनौतियां थीं जिसे आपसी तालमेल से निबटाया गया। जब सिविल और डिफेंस साथ में मिलकर काम करते हैं तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। रक्षामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ की तहजीब के साथ-साथ विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेश में रहने वाले भारतवंशी जब लखनऊ आते हैं, तो यहां के विकास को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विदेश में जब भारत के लोगों से मिलता हूं तो वे यहां के विकास की प्रशंसा करते हैं। यूनेस्को ने लखनऊ को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा दिया है यानि अब यह शहर खान-पान की श्रेणी में भी अव्वल हो गया है। विश्व के समृद्ध खानपान की सूची में लखनऊ को स्थान प्राप्त होना गौरव का विषय है। लखनऊ अब दुनिया की 'मोस्ट लिवएबल सिटी' यानि यह दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गया है, जहां रहने के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल गया है।

बच्चों ने मॉडल बनाकर द्वितीय स्थान प्राप्त कर ग्रामीण प्रतिभा का लोहा मनवाया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहा/ हसनपुरः जिला स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार प्रतियोगिता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुड़नपुर में आयोजित की गई ,जिसमें कंपोजिट विद्यालय सुमाठेर विकास क्षेत्र हसनपुर के बच्चों ने मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त कर ग्रामीण प्रतिभा का लोहा मनवाया। कक्षा 8 के छात्र अमान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एडीएम जनपद अमरोहा ने टैबलेट देकर छात्र को सम्मानित किया गया। इसी के साथ-साथ संविलयन विद्यालय सुमाठेर के राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भी चार बच्चों का चयन हुआ।जिससे पूरे ग्रामीण परिवेश और विद्यालय में खुशी का माहौल है। इस खुशी के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार व उनके स्टाफ ने बच्चों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह ने बताया कि वहां के मॉडल को देखकर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय का सिलेक्शन करना इतना मुश्किल हो गया क्योंकि एक से एक बेहतरीन मॉडल बना हुआ था तथा बच्चों के कॉन्फिडेंस को देखकर आनंद की अनुभूति हुई।श्री सिंह ने बताया कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है केवल कमी है पहचान की, वही अरविंद कुमार ने विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए किचन गार्डन में भी विद्यालय का नाम रोशन किया है क्योंकि विद्यालय में अनेक प्रजाति के वृक्ष लगाकर विद्यालय को सुशोभित किया है। इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अरविंद जी एक आदर्श शिक्षक हैं और पूरी मेहनत व अपने मनोयोग के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष होमपाल सिंह ने बताया कि यह विद्यालय प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाए हुए हैं यह विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उनके स्टाफ की मेहनत को दर्शाता है, उन्होंने बताया कि अरविंद जी व उनकी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ कार्य करती है और सभी बच्चों को खूब मेहनत लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया व अभिभावकों को भी प्रेरित किया कि ग्रामीण अंचल के बेहतरीन विद्यालय में अच्छी शिक्षा का माहौल है इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को संवारने हेतु अधिक से अधिक संख्या में नामांकन कराए ताकि आपके बच्चों की भविष्य को सुधारा जा सके, इसी क्रम में गंगेश्वरी के ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर सिंह ने बताया कि अरविंद कुमार व योगेश कुमार दोनों पारस्परिक स्थानांतरण से गंगेश्वरी ब्लॉक से हसनपुर आए हैं और वहां भी पिपलौती कला व प्राथमिक विद्यालय गुलामपुर में दोनों अध्यापकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उसी का परिणाम यह है कि इस मनोयोग से यहां पर दोनों ने मेहनत कर परिणाम को बरकरार रखा और लगन के साथ बच्चों को पढ़ने व उनके अभिभावकों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। विनोद कुमार गौतम के द्वारा बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता को बहुत सारे प्रश्न करके परखा गया जिसमें बच्चे अपनी कसौटी पर खरे उतरे और अच्छी गुणवत्ता वास्तव में बच्चों ने हासिल की है जिसकी तारीफ की गई। अंत में विद्यालय में आए बाहर से सभी अतिथियों ने चयनित सभी बच्चों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार, योगेश कुमार ,अशोक कुमार ,कविता देवी ,मेहरुल निशा ,लखमी सिंह ,देशवीर सिंह ,ब्रह्म ज्ञान सिंह, अर्से आलम ,कुलदीप कुमार ,नीतू रानी, काफी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।

मजदूर के लिए फरिश्ता बने नवील इलाही, संभल यूथ फोरम की टीम ने घायल हसीन की बढ़ाई मदद की हाथ

लोक तंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल : जिले में इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली, जब मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले हसीन नामक व्यक्ति गंभीर हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि काम के दौरान वह अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी और कुल्हे में गंभीर चोट लग गई। हादसे के बाद हसीन की हालत काफी नाजुक हो गई। हसीन के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं और वह ही अपने परिवार का एकमात्र सहारा हैं। ऐसे मुश्किल समय में नवील इलाही और उनकी पूरी संभल यूथ फोरम की टीम इंसानियत का फर्ज निभाते हुए तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच गई। नवील इलाही और उनकी टीम ने न केवल हसीन का हालचाल जाना, बल्कि हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही असली इंसानियत है। स्थानीय लोगों ने भी नवील इलाही और संभल यूथ फोरम की सराहना करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोग ही उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मानवीय पहल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नवील इलाही और संभल यूथ फोरम हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों के साथ खड़े रहते हैं और समाज सेवा में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जुमतुल विदा पर शिया जुम्मा मस्जिद सिरसी में गूंजी बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की आवाज़ - मौलाना सैयद हसीन अख्तर ज़ैदी बोलेः ईरान पर हमले पर खामोशी इंसानियत के खिलाफ

लोक तंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल /सिरसी मुकद्दस रमज़ान के आख़िरी जुमे जुमतुल विदा के मौके पर शिया जुम्मा मस्जिद सिरसी में बैतुल मुकद्दस (अल-कुद्स) की आज़ादी और पश्चिम एशिया में जारी हिंसा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। इस दौरान शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद हसीन अख्तर ज़ैदी ने ईरान और फिलिस्तीन से जुड़े हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया को ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मौलाना सैयद हसीन अख्तर ज़ैदी ने कहा कि बैतुल मुकद्दस पर इजराइल के कब्जे और फिलिस्तीनी जनता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना हर इंसाफ-पसंद इंसान का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दुनिया के कई देशों की खामोशी इंसानियत के लिए चिंता का विषय है।

अपने बयान में मुंतज़िर मुतवल्ली व पूर्व चेयरमैन मार्केटिंग संभल चौधरी सैयद

मोहम्मद फैजान अली नक़वी बयान में कहाः "हम बैतुल मुकद्दस पर इजराइल के जबरन कब्जे और वहां हो रहे जुल्म के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वहां जो अत्याचार हो रहा है, उसे अमेरिका का खुला समर्थन मिल रहा है। ईरान लगभग निहत्था है, लेकिन अमेरिका उस पर बमबारी कर रहा है और आम लोगों को निशाना बना रहा है। यह बेहद शर्म की बात है कि दुनिया के कई देश इस पर खुलकर आवाज़ नहीं उठा रहे।" इस मौके पर मुतवल्ली चौधरी सैयद सीरत उरूज आलम नक़वी ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि बैतुल मुकद्दस की आज़ादी और फिलिस्तीनी जनता के हक़ की आवाज़ उठाना इंसाफ और इंसानियत की मांग है। वक्ताओं ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक और दोस्ताना रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध सदियों पुराने हैं। ऐसे में दुनिया को चाहिए कि वह युद्ध और हिंसा के बजाय शांति और इंसाफ का रास्ता अपनाए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बैतुल मुकद्दस की आज़ादी, फिलिस्तीन के समर्थन और दुनिया में अमन-चैन के लिए दुआ भी की।

होटल इंद्रलोक के इफ़्तार कार्यक्रम में दिखा गंगा-जमुनी तहज़ीब का नज़ारा, शहर के लोग रहे मौजूद

लोक तंत्र की शान, (खिज़र अहमद)

नजीबाबाद। नगर स्थित होटल इंद्रलोक में मरहूम यामीन सैफी की याद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक भव्य रोज़ा इफ़्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से चली आ रही इस खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके बच्चों व परिजनों ने पूरे सम्मान और जिम्मेदारी के साथ इस आयोजन को संपन्न कराया। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों, पत्रकारों और बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत कर मरहूम यामीन सैफी को याद किया। इफ़्तार कार्यक्रम के दौरान आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का अत्यंत सुंदर माहौल देखने को मिला। रोजेदारों ने एक साथ बैठकर रोज़ा इफ़्तार किया और मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं कीं। उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी मेल-मिलाप और भाईचारे को मजबूत करने का काम करते हैं। बताया जाता है कि मरहूम यामीन सैफी अपने जीवनकाल में भी सामाजिक कार्यों और लोगों को जोड़ने के लिए हमेशा आगे रहते थे।

उनकी इसी सोच और परंपरा को आज उनके बच्चे और परिवार के लोग पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी नगर के लोगों ने सराहना की। इस मौके पर इंसानियत और एकता की मिसाल बने कोटद्वार निवासी मो. दीपक ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन केवल इफ़्तार तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह समाज

में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देने का माध्यम बनते हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इफ़्तार के बाद लोगों ने एक-दूसरे से मुलाकात कर रमज़ान की मुबारकबाद दी और सामाजिक एकता को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर के कई गणमान्य लोग, समाजसेवी, व्यापारी, पत्रकार और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उपस्थित लोगों ने आयोजकों की सराहना भी की।

संक्षिप्त समाचार

138 एलपीजी सिलेंडर जब्त, आरोपी फरार, कालाबाजारी के आरोप पर गोदाम में छापेमारी

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना के दानापुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुरुवार रात अनुमंडल प्रशासन ने शाहपुर थाना क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारा गया। इस दौरान 138 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। इनमें से 25 सिलेंडर भरे हुए थे। एसडीएम अनिरुद्ध पांडेय के निर्देश पर एएसडीओ सहित आपूर्ति विभाग की टीम ने शाहपुर पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। छापेमारी की भनक लगते ही कालाबाजारी में लिप्त लोग मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान जब्त किए गए सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं मिले। इसके बाद टीम ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि ये सिलेंडर किस गैस एजेंसी के थे। आपूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दानापुर के एएसडीओ तेज प्रताप ने बताया कि,'जिलाधिकारी के निर्देश पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर सुचारू रूप से न मिलने की कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसकी लगातार जांच की जा रही थी।' एएसडीओ के अनुसार, इसी क्रम में शाहपुर थाना क्षेत्र में कालाबाजारी के लिए घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी। जिसके बाद यह छापेमारी की गई। उन्होंने यह भी बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

'पवन सिंह के कई अफेयर थे,अक्षरा से लड़ाई होती थी'

लोकतंत्र की शान : पटना। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने पवन- अक्षरा की पर्सनल लाइफ को लेकर नया खुलासा किया है। एक वक्त था जब भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके और पवन सिंह के अफेयर की खूब चर्चा थी। सालों बाद मोनालिसा ने इस पर अपनी बात रखी है। एक इंटरव्यू के दौरान मोनालिसा से पूछा गया कि, आपने 'पवन राजा' और 'सरकार राज' जैसी फिल्मों में पवन सिंह और अक्षरा के साथ काम किया। उस वक्त जब पवन सिंह के साथ आपके अफेयर की चर्चा होती थी तो अक्षरा को क्या फर्क पड़ता था? इस पर मोनालिसा ने कहा कि, मुझे नहीं पता। क्योंकि अक्षरा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। वो लोग सेट पर अपने में ही रहते थे। मोनालिसा ने ये भी कहा कि पवन सिंह को लोग घमंडी और बदतमीज बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। ना ही गलत तरीके से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बी ग्रेड की फिल्में भी की हैं। इंटीमेट सीन में कई एक्टर मुझ पर हावी भी हुए। मोनालिसा ने बताया कि,भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर आपने किसी के साथ 5-6 मूवीज कर ली, तो लोग कहने लगते हैं कि अफेयर हो गया। मैंने जब पवन सिंह और खेसारी के साथ काम किया, तो उनके पहले से अफेयर चल रहे थे। पवन सिंह मेरे साथ जब काम करते थे, तो उनके पहले से बहुत सारे अफेयर चल रहे थे। उस टाइम झगड़े भी होते थे। वैनिटी में उनके झगड़े होते थे और सेट का पूरा माहौल खराब हो जाता था।

बिहार के 5 जिलों में यलो अलर्ट, किशनगंज में तेज बारिश, पटना में चली ठंडी हवा

लोकतंत्र की शान : पटना। बिहार में गुरुवार देर शाम को अचानक मौसम ने करवट ली है। सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज में तेज बारिश हुई। पटना में ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। इसके साथ कई शहरों में मौसम बदला है। मौसम विभाग के अनुसार, 14 से 16 मार्च के बीच उत्तर और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है। इससे गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह बदलाव बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। राज्य में उमस भरी गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने की संभावना कम है। अगले कुछ दिनों तक दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। आज प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री के बीच बना रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। इन जिलों में कहीं-कहीं बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इसके अलावा राज्य के अन्य बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। दिन में तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय बिहार के मौसम पर कई मौसमी प्रणालियों का असर पड़ रहा है। एक ओर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भी वातावरण में बदलाव ला रही है। इसी कारण कुछ इलाकों में अचानक बादल, हवा और हल्की बारिश हो रही है। इसके उलट ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम के इस मिश्रित प्रभाव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

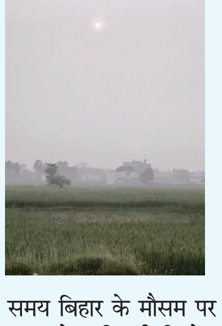

आईजीआईएमएस में 2 दिन की नवजात की क्रिटिकल सर्जरी सफल, पीड़ित बच्ची का 3 घंटे चला ऑपरेशन

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में डॉक्टरों की टीम ने दो दिन की नवजात बच्ची की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की है। बच्ची ट्रेकियो-इसोफेगल फिस्टुला (टीईएफ) नामक जन्मजात बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें श्वासनली और भोजन नली असामान्य रूप से जुड़ी होती हैं। डॉक्टरों ने इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को आधुनिक थोराकोस्कोपी तकनीक और वन-लंग वेंटिलेशन की मदद से पूरा किया। डॉक्टरों के अनुसार, इतनी कम उम्र के नवजात में ऐसी सर्जरी करना बेहद जोखिम भरा और तकनीकी रूप से जटिल होता है। IGIMS की विशेषज्ञ टीम ने लगभग तीन घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्ची को सुरक्षित कर लिया। फिलहाल, नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही है। नवजात बच्ची का जन्म मधुबनी सदर अस्पताल में हुआ था। जन्म के बाद जब परिजन उसे घर ले जा रहे थे, तब बच्ची के सीने में घरघराहट और सांस लेने में परेशानी होने लगी। स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए आईजीआईएमएस रेफर कर दिया था। आईजीआईएमएस पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की जांच की। जांच में उसे ट्रेकियो-इसोफेगल फिस्टुला (टीईएफ) नामक जन्मजात बीमारी होने का पता चला। इस स्थिति में भोजन नली और श्वासनली के बीच असामान्य जुड़ाव हो जाता है, जिससे दूध या भोजन फेफड़ों में जा सकता है और नवजात को सांस लेने में गंभीर समस्या हो सकती है। शिशु शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. विनीत कुमार ठाकुर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। टीम में डॉ. ओम पुर्वे, डॉ. रोहित और डॉ. विवेक रंजन शामिल थे। डॉक्टरों ने आधुनिक थोराकोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन किया। यह एक मिनिमली इनवेसिव तकनीक है, जिसमें बड़े चीरे की जगह छोटे छेद के जरिए कैमरा और सर्जिकल उपकरण डालकर ऑपरेशन किया जाता है। इससे सर्जरी के बाद मरीज को जल्दी रिकवरी मिलती है और संक्रमण का खतरा भी कम होता है। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि इसे वन-लंग वेंटिलेशन तकनीक के साथ किया गया। नवजात शिशुओं में यह प्रक्रिया अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इतने छोटे शरीर में सांस और ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है।

सहरसा में 'समृद्धि यात्रा' के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन संवाद, विकास कार्यों और नई योजनाओं की दी जानकारी

लोकतंत्र की शान

सहरसा, रिपोर्टः मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने समृद्धि यात्रा के तहत सहरसा जिले के सहरसा स्टेडियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा आने वाले वर्षों में राज्य के विकास को और तेज करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में उनकी सरकार बनने के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और राज्य में विकास की गति तेज हुई। उन्होंने कहा कि पहले लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल था, लेकिन अब राज्य में शांति और भाईचारे का वातावरण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य बड़े पैमाने पर कराया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए बताया कि बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए और शिक्षकों की नियुक्ति की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हजारों शिक्षकों की बहाली की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी शिक्षकों की संख्या बढ़कर लगभग 5 लाख से अधिक हो चुकी है और आगे भी नई नियुक्तियां जारी रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब हर महीने हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है और कई नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को और

मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में सड़कों, पुलों और बाईपास का व्यापक निर्माण कराया गया है, जिससे दूर-दराज के इलाकों से पटना तक पहुंचने का समय काफी कम हो गया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि कृषि रोडमैप के माध्यम से राज्य में अनाज, फल, सब्जी, दूध और मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की "सात निश्चय" योजना के तहत हर घर नल का जल, हर घर बिजली, पक्की सड़क और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाखों घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना भी शुरू की गई है। रोजगार के क्षेत्र में सरकार की पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि स्वयं सहायता समूहों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और "जीविका" कार्यक्रम के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे और युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर सुधार किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary, जल संसाधन मंत्री Vijay Kumar Chaudhary, सांसद Dinesh Chandra Yadav, विधायक Alok Ranjan, विधायक Sanjay Kumar Singh सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा 48 घंटे से लापता, परिवार को अपहरण का शक

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना जिले के बिहटा में 20 साल की छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। छात्रा पिछले 48 घंटे से गायब है और उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार ने अपहरण की आशंका जताई है। घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में छात्रा अपने घर की ओर जाती दिखाई दे रही है। इसी दौरान दो युवक पहले से रास्ते में मौजूद नजर आते हैं, जो उसका पीछा करते दिख रहे हैं। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में छात्रा डरकर भागती हुई भी दिखाई दी है।

घर लौटते समय किया था फोनः लापता छात्रा की बड़ी बहन शालिनी कुमारी के मुताबिक, 'मेरी बहन नेहा कॉलेज में पढ़ाई करती है। 11 मार्च को रोज की तरह सुबह 8 बजे लाइब्रेरी क्लास के लिए गई थी। वह श्रीरामपुर टोला स्थित रविदास मंदिर के पीछे वाली गली में पढ़ने जाती थी।

परिवार ने जताई अपहरण की आशंकाः परिवार ने मामले को लेकर बिहटा थाना में लिखित आवेदन दिया है। परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में उनकी बहन भागती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। ऐसे में उन्हें

सीसीटीवी में पीछा करते दिखे दो लड़के, फोन बंद

अपहरण की आशंका है। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी छात्रा का मोबाइल बंद है, जिससे परिवार में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है।

पुलिस कर रही तलाशः बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि, 'छात्रा की मां की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छात्रा की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया है।' उन्होंने बताया कि, 'सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। छात्रा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है।' पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है।

मुख्यमंत्री का फैसला गठबंधन तय करेगा- श्रवण कुमार

निशांत को सीएम बनाने की मांग पर बोले- हर दल चाहता है उसका नेता सीएम बने

लोकतंत्र की शान , पटना

मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य की राजनीति, राज्यसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद को लेकर कई अहम बातें कही हैं। कहा कि, 'मुख्यमंत्री किसका होगा, इसका फैसला बड़े स्तर पर होगा।' उन्होंने कहा कि, 'यह निर्णय गठबंधन में शामिल सभी दल मिलकर करेंगे।' साथ ही उन्होंने राज्यसभा की सभी सीटों पर NDA की जीत का दावा भी किया।

मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या बोले मंत्रीः मंत्री श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उनका होगा। इस पर उन्होंने कहा कि, 'यह सब बड़े स्तर पर तय होगा।' उन्होंने कहा कि, 'जिसने यह बयान दिया है, उसी से जाकर पूछा जाना चाहिए कि उन्हें कैसे पता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा।' मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि, 'हर दल का नेता चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, उनका नेतृत्व आगे आए।'

राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि, 'बिहार में हो रही तरक्की और विकास को देखते हुए विधायक मतदान करेंगे, चाहे वे किसी भी दल के हों।' उन्होंने दावा किया कि, 'महागठबंधन के उम्मीदवार की हार होगी और एनडीए पांचों सीटों पर जीत हासिल करेगा।' उन्होंने बताया कि, राज्यसभा चुनाव को लेकर हाल ही में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।' बिहार में गैस सिलेंडर की कमी की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि, 'कुछ लोग कालाबाजारी करने में लगे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पांचवें उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंसः राज्यसभा की पांचवीं सीट के लिए उम्मीदवार को लेकर शिवेश कुमार राम और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा है। हालांकि, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि, 'उम्मीदवार के नाम का खुलासा उचित समय पर किया जाएगा।'

समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने सहरसा को दी 512 करोड़ की योजनाओं की सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः समृद्धि यात्रा के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने Saharsa जिले का दौरा कर कुल 512 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 286 करोड़ रुपये की लागत से 70 योजनाओं का उद्घाटन, 90 करोड़ रुपये की लागत से 20 योजनाओं का शिलान्यास तथा 136 करोड़ रुपये की लागत से 35 योजनाओं का कार्यारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शाहपुर वार्ड संख्या–7 में जीविका सिलाई सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया तथा जीविका दीदियों से बातचीत कर उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के

सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान जीविका समूहों को करोड़ों रुपये की सहायता राशि का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया गया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने लाभुकों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में वृद्धजन पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, कन्या उत्थान, अल्पसंख्यक कल्याण सहित कई योजनाओं के लाभुकों को स्वीकृति पत्र और सहायता राशि दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सहर्षा शहर में प्रस्तावित रेलवे समपार फाटक पर आरओबी निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आरओबी बनने से शहर में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी तथा एनएच-107 से मधेपुरा और सुपौल जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने मण्डन मिश्र धाम, उग्रतारा मंदिर, स्टेडियम निर्माण, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, मत्स्यगंधा झील सौंदर्यीकरण सहित कई विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद दिनेश चंद्र यादव, विधान पार्षद ललन सर्राफ, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, कोसी प्रमंडल आयुक्त राजेश कुमार, आईजी कुमार आशीष, जिलाधिकारी वैभव चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक हिमांशु सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकारी अस्पतालों में गैस संकट, 10 दिन से कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति ठप होने से सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर असर पड़ने लगा है। पिछले करीब 10 दिनों से सिलेंडर नहीं मिलने के कारण कई बड़े अस्पतालों के किचन और हॉस्टल मेस में भोजन बनाने में परेशानी हो रही है। इसका असर PMCH, IGIMS, NMCH और LNJP हड्डी अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर मरीजों और मेडिकल छात्रों के लिए इंडक्शन चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है।

इंडक्शन चूल्हों से बनाई जा रही रसोईः समस्या के समाधान के लिए बुधवार देर रात पीएमसीएच और आईजीआईएमएस के मेस में इंडक्शन चूल्हे मंगाए गए। गुरुवार सुबह से मरीजों और छात्र-छात्राओं के लिए भोजन इन्हीं इंडक्शन चूल्हों पर तैयार किया जा रहा है। पीएमसीएच के धनवंतरी हॉस्टल के एक मेडिकल छात्र ने बताया कि गैस आपूर्ति बाधित होने से मेस में भोजन बनाने में दिक्कत होने लगी थी। छात्रों के विरोध के बाद तत्काल इंडक्शन चूल्हों की व्यवस्था की गई, जिससे रोटी समेत अन्य भोजन तैयार किया जा सका। पीएमसीएच के डीएच-1, जीवक और चाणक्या हॉस्टल के मेस के साथ-साथ आईजीआईएमएस और एनएमसीएच के हॉस्टलों में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल में जीविका के माध्यम से प्रतिदिन करीब 2000 मरीजों के लिए भोजन तैयार किया जाता है।

पटना नगर निगम कर्मी करेंगे नगर आयुक्त का घेराव

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना नगर निगम के कर्मी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री के सामने विशाल प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले 30 मार्च को निगम मुख्यालय मौर्या लोक में नगर आयुक्त का घेराव किया जाएगा। यह जानकारी पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष नन्द किशोर दास ने दी। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और राज्य सरकार मजदूर विरोधी हैं। उनके वादा खिलाफी के विरुद्ध हर सफाई कर्मी के मन में काफी आक्रोश है।

सफाई कर्मचारियों ने अपनी 9 मांगों को लेकर मोर्चा खोला है। उनमें बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन, तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर जमे कर्मचारी अधिकारियों को अविलंब ट्रांसफर किया जाना, निजीकरण समाप्त कर स्थाई बहाली करने की मांग शामिल है। इसके अलावा दैनिक कर्मियों कि सेवा स्थाईकरण, सेवानिवृत्त और मृत कर्मियों के सभी बकाया राशि का भुगतान, एमएसीपी लाभ का भुगतान करने, समान काम के समान वेतन लागू करने, निजी एजेंसी के अधीन काम कर रहे सफाई मजदूरों को कुशल मजदूरी भुगतान, वर्दी की राशि भुगतान करने सहित अन्य मांगें हैं।

एनडीए विधायकों की सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एनडीए विधानमंडल दल की अहम बैठक उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हुई। बैठक में गठबंधन के सभी घटक दलों के विधायक शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा की पांचों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही विधायकों को मतदान की प्रक्रिया और उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नेताओं ने कहा कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है और गठबंधन राज्यसभा की सभी पांचों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। विपक्ष की ओर से एक सीट जीतने के दावे को लेकर भी चर्चा हुई और विधायकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।

विधायकों को दिया गया मतदान का प्रशिक्षणः बैठक में बताया गया कि राज्यसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया सामान्य चुनाव से अलग होती है। इसलिए सभी विधायकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई नए विधायक भी पहली बार राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, इसलिए उन्हें वोटिंग के नियम और तकनीकी पहलुओं के बारे में समझाया गया। नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह का चुनाव हो रहा है, इसलिए सभी को विस्तार से जानकारी दी जा रही है कि वोटिंग कैसे करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है।

एनडीए ने राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें करने का फैसला किया है। 14 मार्च को विधायकों की बैठक उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित होगी, जहां वोटिंग प्रक्रिया को लेकर फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अगले दिन 15 मार्च को जदयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी के आवास पर भी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव तक पटना में ही रहें और किसी को भी पटना से बाहर नहीं जाना है।

मुख्यमंत्री को लेकर बयान से सियासत गरमः बैठक के बाद बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान के एक बयान से सियासी चर्चा तेज हो गई। उन्होंने कहा कि, 'बिहार में जब भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, तो वह भाजपा का ही होगा। एनडीए के भीतर भी यही इच्छा है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा से हो। हालांकि, इस बयान पर जदयू की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया भी सामने आई। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि, 'ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लोग अक्सर अनुमान के आधार पर ऐसी बातें कहते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है।' बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के दौरान भावुक होने की घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए लंबे समय तक काम किया है और उनका जनता से गहरा जुड़ाव है। ऐसे में उनका भावुक होना स्वाभाविक है।

संक्षिप्त समाचार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनेगा अत्याधुनिक एमआरओ हब, आकासा एयर के साथ हुआ रणनीतिक समझौता

लोकतंत्र की शान : नोएडा। उत्तर प्रदेश तेजी से देश के प्रमुख निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभर रहा है। इसी क्रम में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देश की तेजी से उभरती एयरलाइन आकासा एयर के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी हुई है। इसके तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में अकासा एयर की पहली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा स्थापित की जाएगी। यह अत्याधुनिक एमआरओ केंद्र विमान रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी सेवाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार करेगा। इससे भारत के एविएशन सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश-प्रोत्साहन नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के चलते उत्तर प्रदेश में वैश्विक कंपनियों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विकसित हो रही यह एमआरओ सुविधा प्रदेश को एविएशन, लॉजिस्टिक्स और हाईटेक इंडस्ट्री के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परिचालन लागत और समय में आएगी कमी-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आकासा एयर के बीच यह साझेदारी न केवल देश में विमान रखरखाव की क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को एविएशन मेंटेनेंस और तकनीकी सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी। इस एमआरओ सुविधा के विकसित होने से विमान कंपनियों को देश के भीतर ही उच्च गुणवत्ता वाली मेंटेनेंस सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे परिचालन लागत और समय में कमी आएगी। रोजगार और कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा-इस अत्याधुनिक एमआरओ सुविधा के स्थापित होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय युवाओं को एविएशन टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से जुड़े कौशल प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही यह परियोजना क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। यूपी को एविएशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम-यह पहल भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के उस विजन के अनुरूप है, जिसके तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के प्रमुख एमआरओ हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे भारत की विमानन सेवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता मजबूत होगी।

नारनौल से चित्तौड़गढ़ के लिए नई बस सेवा शुरू

लोकतंत्र की शान : नारनौल। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा कनीना से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक नई बस सेवा शुरू की गई है। हरियाणा राज्य परिवहन नारनौल डिपो के जीएम देवदत्त ने शुक्रवार को बताया कि यह बस सेवा रोजाना चलाई जाएगी। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बस सेवा से क्षेत्र के लोगों को राजस्थान जाने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। जीएम देवदत्त ने बताया कि यह बस प्रातः सात बजे कनीना से रवाना होगी और करीब आठ बजकर 40 मिनट पर नारनौल पहुंचेगी। इसके बाद बस जयपुर, टोंक, देवली और बेगू होते हुए रात लगभग 10 बजकर 15 मिनट पर चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि कनीना से चित्तौड़गढ़ तक की यात्रा में करीब 15 घंटे का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ से वापसी में बस अगले दिन प्रातः चार बजकर 15 मिनट पर रवाना होगी और शाम करीब पांच बजकर 45 मिनट पर नारनौल पहुंचेगी। इस बस सेवा से हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ का परमिट पहले से विभाग के पास था, लेकिन काफी समय से यह सेवा बंद पड़ी हुई थी। परिवहन विभाग की ओर से किलोमीटर बढ़ाने के निर्देश मिलने के बाद इस रूट को दोबारा शुरू किया गया है। लोगों ने इस बस सेवा के शुरू होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बस सेवा से हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। साथ ही क्षेत्र के लोगों को राजस्थान जाने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इस नई बस सेवा से कनीना, नारनौल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को राजस्थान के प्रमुख शहरों तक सीधी बस सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिलावासियों ने इस नई बस सेवा को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का धन्यवाद व्यक्त किया है।

सिरसाः दो सड़क हादसों में तीन की मौत

लोकतंत्र की शान : सिरसा। सिरसा जिले में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शवों का शुक्रवार को सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। सिरसा जिले के गांव केहरवाला के पास गुरुवार रात दो कारों की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों कार चालकों की मौत हो गई, जिनकी पहचान संतनगर निवासी बलवंत सिंह व केहरवाला निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई है। जबकि माया देवी पत्नी बलवंत सिंह जो कि आंगनवाड़ी वर्कर है, गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार डबवाली से जीवननगर की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार केहरवाला से डबवाली की तरफ जा रही थी। गांव केहरवाला के पास दोनों कारों में सीधी टक्कर हो गई। बलवंत सिंह पत्नी माया देवी के साथ डबवाली में शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर नगारिक अस्पताल भिजवाया, जहां शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के अनुसार मृतक विनोद कुमार राजमिस्त्री का काम करता था। उधर, सिरसा-भादरा मार्ग पर गुरुवार रात्रि को एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। उसे घायलावस्था में उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव अरनियांवाली निवासी अजय के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर चोपटा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। अजय कुमार किसी काम से गांव शेरपुरा में गया हुआ था। रात्रि करीब साढ़े दस बजे वह बाइक पर घर वापस आ रहा था। 8 वां मील बस स्टेंड के निकट उसकी मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो कारीगरों को कुचला, दर्दनाक मौत

» शहर के पटेल पुल के पास हुआ भीषण सड़क हादसा

लोकतंत्र की शान

सीधी। शहर के पटेल पुल के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में दो कारीगर मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सतना जिले के निवासी दोनों मजदूर कारीगर घरों और दुकानों में ग्रेनाइट लगाने का काम करते थे। हादसे की सूचना देर गुरूवार रात करीब 2 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मिली जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर बस से उतरकर सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार काले रंग की अज्ञात स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद रात भर दोनों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे मृतकों की पहचान हो पाई। मृतकों में बसंत यादव 40 वर्ष और रामभुवन सिंह 65 वर्ष शामिल हैं, जो सतना जिले के निवासी थे। दोनों सीधी शहर में मजदूरी कर घरों और दुकानों में ग्रेनाइट लगाने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर सतना से सीधी काम के सिलसिले में आ रहे थे और बस से उतरने के बाद सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दादर में अंतर्राज्यीय वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज से

लोकतंत्र की शान

सीधी। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी मझौली ब्लॉक के ग्राम दादर जोगीपहाड़ी में अन्तराज्यीय वालीबॉल टूर्नामेंट का 2 दिवसीय आयोजन आज 14 एवं कल 15 मार्च को आयोजित किया जायेगा, जिसका उद्घाटन आज 3 बजे किया जायेगा। रात्रि 10 बजे तक बालीबाल शा.पू.मा. विद्यालय खासाडोल दादर में खेला जायेगा एवं कल 15 मार्च को धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम के मुख्य अतिथि, जनपद अध्यक्ष मझौली सुनैना सिंह, जनपद अध्यक्ष कुसमी श्यामबती सिंह के विशिष्ट अतिथि सहित अन्य अतिथियों कि उपस्थिती में सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगातार मुकाबला होगा और 15 को ही फाइनल मुकाबला खेला जायेगा। इस टूर्नामेंट में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, एवं मध्यप्रदेश के कुछ बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही है।दादर स्पोर्ट्स एवं म्यूजिक संस्थान द्वारा प्रायोजित टूर्नामेंट का आयोजन पूर्ण रूप से जनसहयोग से हो रहा है।दादर स्पोर्ट्स के संचालक कनक द्विवेदी ने मैच देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में दर्शकों के पहुंचने की अपील की है।

एचपी गैस एजेंसी पर ग्राहकों का हंगामा, लंबी लाइन से परेशान उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा – वीडियो वायरल

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ कटनी जबलपुर मध्य प्रदेश

कटनी । जिले में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी उस समय खुलकर सामने आ गई जब शहर की पुरुषोत्तम एचपी गैस एजेंसी के बाहर ग्राहकों ने जमकर हंगामा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एजेंसी के सामने इकट्ठा होकर नाराजगी जताते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को कई दिनों से एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। शुक्रवार को भी जब बड़ी संख्या में लोग गैस लेने पहुंचे तो एजेंसी के बाहर लंबी कतार लग गई। घंटों इंतजार के बाद भी जब कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने एजेंसी के सामने हंगामा शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह से ही एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ लगने लगी थी। महिलाएं और बुजुर्ग भी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन गैस वितरण की धीमी व्यवस्था के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि एजेंसी में समय पर गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार लौटना पड़ रहा है। हंगामे के दौरान कई उपभोक्ताओं ने एजेंसी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधारने की मांग की। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

आपूर्ति कम बताकर उपभोक्ताओं को लूटने का खेल-ज्ञान सिंह

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। ज्ञान सिंह ने कहा कि जिले सहित कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी-लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी कई स्थानों पर बाधित हो रही है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार का दावा सही है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो फिर जनता को इस तरह की परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दो ही संभावनाएं नजर आती हैं या तो भाजपा सरकार वास्तविक स्थिति को छिपाकर झूठ बोल रही है, या फिर कुछ गैस एजेंसी संचालक और पेट्रोल पंप संचालक आपूर्ति कम बताकर कालाबाजारी कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को लूटने का सुनियोजित खेल चल रहा है। ज्ञान सिंह ने कहा कि यदि कहीं भी कृत्रिम संकट पैदा कर कालाबाजारी की जा रही है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है और प्रशासन को तत्काल इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की जरूरत की वस्तुओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की कि जिले में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की स्थिति की पारदर्शी जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि समस्या वास्तव में आपूर्ति की है या फिर जानबूझकर संकट पैदा कर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं करता है, तो कांग्रेस आम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कांग्रेस पार्टी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, देर से आई एम्बुलेंस रास्ते में हुआ प्रसव

» कुसमी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शुक्रवार 13 मार्च की सुबह एक गर्भवती महिला को समय पर एंबुलेंस और अस्पताल में स्टाफ नहीं मिलने के कारण रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। घटना के बाद ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवार का है। यहां की निवासी सुमित्रा रजक पति शिवराज रजक, गर्भावस्था के नौवें महीने में थीं। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे से उन्हें तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजनों ने तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा पर संपर्क कर अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद मांगी। परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस बुलाने के बाद भी लगभग 30 से 40 मिनट तक कोई वाहन नहीं पहुंचा। लगातार दर्द बढ़ने पर परिजनों ने मजबूरी में एक निजी वाहन किराए पर लिया और कुसमी अस्पताल के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा तेज हो गई और महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद किसी तरह परिजन प्रसूता और नवजात को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी पहुंचे। वही परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर वहां कोई जिम्मेदार स्टाफ मौजूद नहीं था, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुसमी क्षेत्र में न तो समय पर एंबुलेंस उपलब्ध होती है और न ही अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ रहता है, जिससे मरीजों को लगातार परेशानी उठानी पड़ती है। यदि रास्ते में प्रसूता या नवजात के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जहा ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब इस मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकट सिंह ने बताया कि वे किसी मीटिंग के सिलसिले में सीधी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 108 एंबुलेंस भोपाल स्थित कंट्रोल रूम से संचालित होती है। अस्पताल में स्टाफ की उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि वापस लौटने के बाद पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यमुनानगरःआबकारी विभाग के 90 लाख के डिमांड ड्राफ्ट में गड़बड़ी, फर्म मालिक पर धोखाधड़ी का केस

लोकतंत्र की शान

यमुनानगर। यमुनानगर के जगाधरी में आबकारी विभाग से जुड़े 90 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के मामले में कथित गड़बड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विभाग की शिकायत पर थाना शहर जगाधरी पुलिस ने एक फर्म के प्रोपराइटर के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि बैंक के संबंधित कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई गई है। आबकारी निरीक्षक मोहन सिंह राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मैसर्स एस.एम. वाइन के एल-1 लाइसेंस से जुड़े एक ब्रीच मामले को सात नवंबर 2023 को कलेक्टर (आबकारी) हरियाणा को भेजा गया था। इसके बाद फर्म की ओर से अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी, परमिट फीस और स्टॉक में अंतर की राशि के रूप में 90 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आठ नवंबर 2023 को विभाग में जमा कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर (आबकारी) ने 20 नवंबर 2023 को फर्म पर 2 करोड़ 55 लाख 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए एल-1 लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। इसके खिलाफ फर्म मालिक ने अदालत में याचिका दायर की, जिस पर एक दिसंबर 2023 को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बाद में चार मार्च 2024 को अदालत ने इस आदेश को आगे भी जारी रखा। शिकायत के अनुसार विभागीय रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया कि 90 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दो दिसंबर 2023 को जीआरएन के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगाधरी शाखा में सरकारी खाते में जमा कराया गया था। हालांकि बाद में विभागीय जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त राशि वास्तव में सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। जांच के लिए उप आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा बैंक से प्राप्त जानकारी में बताया गया कि चालान में कथित त्रुटि सुधार के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट खरीदार को वापस कर दिया गया था। शिकायत में फर्म के प्रोपराइटर कपिल और बैंक कर्मचारियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कटनी में खुलेआम बिक रहा कैश पान मसाला / गुटखा लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी निगरानी में यह लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है?

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी : शहर की कई दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहे कैश पान मसाला को देखकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पैकेट पर न तो इसमें मिले अवयवों का स्पष्ट उल्लेख दिखाई देता है, न ही इसके निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट का ठीक से जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, पैकेट पर लाइसेंस नंबर तक का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, जो किसी भी खाद्य या तंबाकू उत्पाद के लिए बेहद जरूरी होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पैकेट पर इतनी अहम जानकारियां ही नहीं हैं, तो आखिर यह उत्पाद किस आधार पर बाजार में बेचा जा रहा है? इतना ही नहीं, पैकेट पर इसकी कीमत 18 रुपये लिखी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दुकानों पर इसे 20 रुपये में बेचा जा रहा है। जबकि नियम साफ कहते हैं कि किसी भी उत्पाद को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचना कानून का उल्लंघन है। इसके बावजूद खुलेआम यह खेल जारी है और जिम्मेदार विभाग शायद आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? कटनी के नागरिकों का कहना है कि इस तरह के संदिग्ध उत्पाद न केवल लोगों की जेब पर बोझ डाल रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब तक चुप्पी साधे रहता है, या फिर जांच कर ऐसे उत्पादों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृह जिला पहुंचे युवा लेफ्टिनेंट, नागरिकों ने किया गर्म जोशी से स्वागत अभिनंदन

लोकतंत्र की शान

सीधी (ऋचा पाण्डेय की रिपोर्ट)। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होने के बाद सीधी जिले के चुरहट विधानसभा के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के सगौनी भरतपुर के युवा ने सेना की सभी आहर्ताए पूरी कर चयनित होने के बाद प्रशीक्षण पूरा कर गुरुवार को अपने गृह जिला आए जहां जनता ने उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया है। लेफ्टिनेंट देवांश पाण्डेय पिता राकेश पाण्डेय गुरुवार को जबलपुर आकर सड़क मार्ग से अपने गृह जिला पहुंचे जहां की जनता ने अपने लाडले के स्वागत में पलक पांवड़े बिछाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी रीवा अमरकंटक मार्ग के कैमोर पहाड़ छुहिया घाट के शिखर से लेकर प्राचीन हनुमान मंदिर कपुरी कोठार एवं देवांश के पैतृक गांव सगौनी तक स्वागत करने वालों की कतार लगती रही सभी अपने लाडले को देखने और दुलार करने शुभकामनाएं देने के लिए उतावले दिखे । लेफ्टिनेंट देवांश मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं उनके पिता राकेश पाण्डेय जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं तो माता श्रीमती रमा पाण्डेय जनपद सदस्य रहने के बाद शिक्षक का दायित्व निर्वहन कर रही है, चाचा प्रकाश पाण्डेय शिक्षक है तो बड़े भाई जबलपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता का निर्वाहन कर रहे। देवांश अपने परिवार के पद चिन्हों पर चलते हुए देश की सेवा करने का संकल्प लिया उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए सेना के आफीसर रैंक की तैयारी किए गत वर्ष हुए परीक्षा में बैठकर अच्छे रैंक से पास किए जिसके बाद उनका चयन लेफ्टिनेंट के लिए किया जाकर प्रशीक्षण के लिए चेन्नई बुलाकर उन्हें दक्ष किया गया,प्रशीक्षण के बाद उनके माता-पिता का जहां सम्मान किया गया वहीं कुछ दिनों के अवकाश पर उन्हें घर भेजा गया है , देवांश चेन्नई से 11मार्च को चलकर जबलपुर पहुंचे जहां से सड़क मार्ग से से 12मार्च 26को अपने गृह जिले में प्रवेश किए,तो जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका ने एच-1बी वीजा देने की प्रक्रिया में बदलाव किया, अब सैलरी के आधार पर होगा चयन

नई दिल्ली। अमेरिका ने एच-1बी वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर होगा। इसके लिए अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने फॉर्म I-129 का नया सिस्टम बनाया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए दाखिल याचिका में नौकरी से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इससे पहले की तुलना में ज्यादा अनुभवी और हाई सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल्स को वीजा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नए सिस्टम में आवेदकों को चार वेतन स्तरों में बांटा जाएगा। जिस पद का वेतन स्तर जितना ऊंचा होगा, चयन प्रक्रिया में उसे उतने अधिक मौके मिलेंगे। मसलन, लेवल-4 के उम्मीदवार को चार मौके मिलेंगे, जबकि लेवल-1 को सिर्फ एक मौका मिलेगा। फॉर्म I-129 का उपयोग अस्थायी कामगारों को अमेरिका बुलाने के लिए किया जाता है। अमेरिका का श्रम विभाग हर पेशे और शहर के लिए एक मानक वेतन तय करता है। उसी के आधार पर नौकरी को लेवल-1 से लेवल-4 में रखा जाता है। ट्रम्प के आदेश का क्या असर- भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल कुल जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजा में से 70% भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किए जाते हैं। एच-1 बी वीजा की फीस कितनी- पहले फीस लगभग 9 हजार डॉलर यानी करीब 8 लाख 30 हजार रुपए थी, लेकिन सितंबर 2025 में ट्रम्प ने इसे बढ़ाकर 1 लाथ डॉलर यानी लगभग 90 लाख रुपए कर दिया। इस वीजा की अवधि कितनी है- 3-3 साल के लिए दो बार जारी होता है। कुल अवधि 6 साल के बाद आवेदक चाहे तो ग्रीन कार्ड यानी नागरिकता से पहले की स्टेज के लिए आवेदन कर सकता है।

चीन की रेडक्रॉस सोसाइटी ईरान की आईआरसीएस को 2 लाख डॉलर की मदद देगी

बीजिंग/मॉस्को। ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के सैन्य टकराव के बीच चीन की रेडक्रॉस सोसाइटी ने ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी (आईआरसीएस) को आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर 2,00,000 अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। चीन ने ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर हाल ही में हुए हमले में छात्रों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उधर, रूस की तरफ से राष्ट्रपति के आदेश पर अजरबैजान के रास्ते भेजी गई 13 टन मानवीय सहायता ईरान के अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर हमले में छात्रों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन की रेडक्रॉस सोसाइटी ने ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर 200,000 अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु (एए) ने रूस के आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से गुरुवार को बताया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर अजरबैजान के रास्ते ईरान को 13 टन मानवीय सहायता भेज गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दवाओं वाली यह खेप अज़रबैजान को सौंप दी गई है, ताकि इसे आगे ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके।बयान में कहा गया है कि मंत्रालय के विमानन विभाग ने दवाओं को अजरबैजान गणराज्य तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया, ताकि उन्हें आगे इस्लामिक गणराज्य ईरान की सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों को सौंपा जा सके।

ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने का दावा

इस्तांबुल/वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के भीषण होते सैन्य टकराव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन (सीवीएन-72) को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने अभी तक ईरान के दावे की पुष्टि नहीं की है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु (एए) के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन (सीवीएन-72) को भारी नुकसान पहुंचाया है। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी नौसेना के इस विमानवाहक पोत को निशाना बनाया गया। लेकिन हमले से हुए नुकसान या संभावित हताहतों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। इसी बीच, अमेरिकी टेलीविजन और रेडियो प्रसारक कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम (सीबीएस) ने नाम नहीं छापने की शर्त पर दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में एक अलग घटना में एक ईरानी जहाज अमेरिकी विमानवाहक पोत अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के काफी करीब पहुंच था। अमेरिकी नौसेना ने उस जहाज को दूर रहने की चेतावनी देने के लिए कार्रवाई की। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि एक अमेरिकी युद्धपोत से ईरानी जहाज पर नौसैनिक तोप से गोलीबारी की गई। पूरी तरह ऑटोमैटिक यह नौसैनिक तोप आमतौर पर डिस्ट्रॉयर और क्रूजर जहाज़ों के आगे के हिस्से में लगाई जाती है। हालांकि, शुरुआती गोलीबारी के दौरान निशाना चूक गया था। फिलहाल, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ये गोलियां चेतावनी के तौर पर चलाई गई थीं या सीधे हमले के लिए। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हेलफायर मिसाइलों से लैस सैन्य हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसने ईरानी जहाज की ओर दो मिसाइलें दागीं। इस संबंध में अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि उस जहाज को कितना नुकसान हुआ या उसके चालक दल की क्या स्थिति है। अमेरिकी सैन्य अभियानों की निगरानी करने वाली इकाई अमेरिकी सेंट्रल कमांड से जब इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि फिलहाल उनके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।

फोरेंसिक जांच से खुलासा- नेपाल में जेन जी विद्रोह के दौरान आगजनी में इस्तेमाल हुआ था पेट्रोलियम पदार्थ

काठमांडू। नेपाल में पिछले वर्ष ८-९ सितंबर को हुए जेन–जी आंदोलन के दौरान संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, देश के प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबार और राष्ट्रपति भवन में आग लगाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ के उपयोग की पुष्टि फॉरेंसिक परीक्षण से हुई है। इन प्रदर्शनों के दौरान संसद भवन के बाहर 17 सहित कुल 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके विरोध में ९ सितंबर को देशभर में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे। जेन–जी आंदोलन के दौरान आगजनी वाले स्थानों से राख और कोयले के टुकड़े, जली हुई मिट्टी, जले हुए तारों के टुकड़े, आधे जले लकड़ी के टुकड़े और आधे जले कपड़ों के नमूने सहित कुल 15 नमूने अलग-अलग जिप-लॉक प्लास्टिक में पैक किए गए थे। इसके साथ ही 12 मिलीलीटर पीले रंग का तरल पदार्थ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखकर भारत के दिल्ली भेजा गया था। ये सभी नमूने सीलबंद कार्टन में रखकर, बाहर से कपड़ा लपेटकर और टेप से सील करके भेजे गए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान जले हुए भवनों से एकत्र किए गए १५ नमूनों की जांच भारत के गृह मंत्रालय के अधीन सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में की गई। जांच में पेट्रोलियम पदार्थ के अवशेष पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूनों में पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन) के अवशेष मिले हैं। परीक्षण के लिए भेजा गया एक तरल नमूना पेट्रोल ही था। प्रयोगशाला में इन १५ नमूनों की जांच भौतिक-रासायनिक विधि, रासायनिक परीक्षण, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी और गैस क्रोमैटोग्राफी–मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तकनीक के माध्यम से की गई, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों और उनके अवशेषों की पहचान हुई। विशेषज्ञों के अनुसार यदि आग लगी जगह से लिए गए नमूनों में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, तो यह पेट्रोलियम पदार्थ के इस्तेमाल का संकेत होता है।अमेरिका की व्योमिंग विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में पीएचडी करने वाले काठमांडू इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस के वरिष्ठ वैज्ञानिक वसंत गिरी ने कहा कि जिस नमूने में पेट्रोलियम पदार्थ के अवशेष होते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं और हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम पदार्थों में ही मिलता है।

बांग्लादेश में दो बसों में टक्कर दूल्हा-दुल्हन समेत 14 की मौत

एजेंसी, ढाका

बांग्लादेश में मोंगला-खुलना हाइवे पर बांग्लादेश नेवी की एक बस और एक यात्री मिनसी बस के बीच आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दूल्हा-दुल्हन और एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। यह हादसा गुरुवार शाम करीब 4:00 बजे बेलाई पुल के पास हुआ। मिनी बस में शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के सदस्य सवार थे। विपरीत दिशा से आ रही नेवी की बस से मिनी बस की टक्कर के बाद चीख-पुकार मच गई।

बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों ने बाद में अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में मोंगला उपजिला के वार्ड नंबर आठ से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अब्दुर रज्जाक, उनके बेटे और दूल्हे सब्बीर, दुल्हन मारजिया अख्तर मितु, मितु की दादी अनवारा बेगम, रज्जाक की पत्नी अंजुमारा बेगम, उनकी बेटियां लामिया और आइशी, आइशी के पति सामियुल, बहू पुतुल, पुतुल का बेटा अलीफ, ईरान, मिनी बस का ड्राइवर नईम, इब्राहिम सानी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।

काटाखाली हाइवे पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी मो. जफर अहमद ने बताया कि कोयरा से मोंगला की

बीएनपी नेता के घर मातम

ओर जा रही मिनी बस की टक्कर नेवी की बस से हो गई। टक्कर में मिनी बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल डॉक्टर महनाज मोशर्रफ ने बताया कि एक ही परिवार के कई घायलों को अस्पताल लाया गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

रूपसा उपजिला स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर राजेश ने बताया कि चार शवों को अस्पताल में रखा गया है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि अब्दुर रज्जाक अपने छोटे बेटे सब्बीर की शादी कोयरा उपजिला के नक्शा गांव की मारजिया अख्तर मितु से करवाने के बाद रिश्तेदारों के साथ घर लौट रहे थे। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक है।

सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल 35 दिन के भीतर चुनाव खर्च का विवरण सार्वजनिक करें: चुनाव आयोग

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अपने चुनाव खर्च का विवरण 35 दिन के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने आय-व्यय के इस विवरण को सार्वजनिक भी करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि चुनाव सम्पन्न होने की तिथि से 35 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के समक्ष और उम्मीदवारों को अपने जिले के प्रादेशिक/जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव प्रचार-प्रसार से संबंधित आय-व्यय का पूरा विवरण जमा करना होगा। साथ ही यह भी जानकारी देनी होगी कि उक्त विवरण सार्वजनिक किया गया है।

आयोग ने राजनीतिक दलों से अपने चुनावी खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। यह विवरण अपने जिले के प्रादेशिक/जिला निर्वाचन कार्यालय के सूचना बोर्ड, संबंधित गाँवपालिका, नगरपालिका या वार्ड कार्यालय के सूचना बोर्ड, राजनीतिक दल के किसी भी स्तर के कार्यालय या वेबसाइट,

आम संचार माध्यमों (अखबार, रेडियो, टेलीविजन आदि) या सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि) के माध्यम से सार्वजनिक किया जा सकता है।

आयोग ने चेतावनी दी है कि जो राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनावी खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे या विवरण सार्वजनिक करने के प्रमाण सहित लिखित जानकारी आयोग तथा संबंधित निर्वाचन कार्यालय को नहीं देंगे, उनके खिलाफ निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन की धारा 31 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन की धारा 31 की उपधारा (2) के अनुसार चुनावी खर्च का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से सार्वजनिक करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके।

वाराणसी स्टेशन पर 3.54 करोड़ का सोना बरामद

दो गिरफ्तार, अफ्रीका से बांग्लादेश होते हुए पहुंचा था भारत

एजेंसी, वाराणसी

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से जीआरपी थाना के पुलिसकर्मियों ने दो किलो से अधिक सोना बरामद किया है। यह सोना अफ्रीका से बांग्लादेश होते हुए भारत पहुंचा था। इस मामले में जीआरपी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

जीआरपी कैंट थाना के निरीक्षक राजोल नागर ने बताया कि महाराष्ट्र के सातार के निवासी बालासो व पूना निवासी तेजस को कैंट रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ा है। यह दोनों शातिर किस्म के हैं और अक्सर इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं। उन्होंने

बताया कि दोनों युवकों के पास से दो किलो से अधिक सोने के बिस्किट बरामद किये गए। बरामद

सोने की कीमत करीब 3.54 करोड़ के करीब बताई जा रही है। इनके पास से बरामद सोना विशेष रूप से अफ्रीकी सोना है। पूछताछ में पता चला कि दोनों अफ्रीका से बांग्लादेश के रास्ते सोना लेकर भारत पहुंचे थे। जीआरपी पुलिस दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर जवाबी हमला

एजेंसी, इस्लामाबाद

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अफगान वायुसेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला किया। मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की बीती रात किए गए हमलों के जवाब में की गई। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कोहाट क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। साथ ही सैन्य किले को भी निशाना बनाया गया। हालांकि हमले से किसी के मारे जाने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल, पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबूल और कंधार में हवाई हमले किए थे। तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक, हमले में 6 लोगों की मौत और 15 घायल हुए हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल है। साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।

पाकिस्तान ने अफगान के फ्यूल डिपो पर हमला किया था: तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक, पाकिस्तान ने प्राइवेट एयरलाइन 'काम एयर' के फ्यूल डिपो पर हमला किया था, जो सिविलियन विमानों और UN के विमानों को भी फ्यूल सप्लाई करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने

रॉयटर्स को बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी तालिबान (TTP) के ठिकानों पर की गई है। हाल के महीनों में देश में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया।

पाकिस्तान ने तालिबान नेताओं के गढ़ को निशाना बनाया: तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पाकिस्तानी हमले कंधार और पक्तिका प्रांतों में भी किए गए। कंधार तालिबान नेताओं का गढ़ माना जाता है। वहीं, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल, पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वह अपनी जमीन

❑ खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बीती रात पाकिस्तानी हमले में 6 अफगानी मारे गए

का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को न करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयरस्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया था कि सीमावर्ती इलाकों में TTP के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह संख्या 80 तक पहुंचने का दावा किया था। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान को 'सही समय पर कड़ा जवाब' दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने हरिद्वार में पांच मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को किया समर्पित

एजेंसी, हरिद्वार

केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को बीएचईएल हरिद्वार उपनगरी में नवनिर्मित 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बीएचईएल की सीएफएफपी इकाई में 30 टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का भी उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बीएचईएल हरिद्वार की निर्मित 53वीं एसआरजीएम नेवल गन की खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बीएचईएल के हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। केंद्रीय मंत्री

कुमारस्वामी ने बीएचईएल हरिद्वार की निर्मित 53वीं एसआरजीएम नेवल गन के संबंध में कहा कि यह नेवल गन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह नेवल गन 35 किलोमीटर के दायरे में, हवा और पानी में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेद सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बीएचईएल हरिद्वार की सीएफएफपी इकाई में 30 टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का भी उद्घाटन किया। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि बीएचईएल धा स्थापित यह फर्नेस, देश के भारी उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी साबित होगी। इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन में मदद मिलेगी, जिससे बड़े आकार के कास्टिंग एवं फोर्जिंग की गुणवत्ता और दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री ने अडानी पावर लिमिटेड के रायपुर प्रोजेक्ट की यूनिट-1 के लिए निर्मित 800 मेगावॉट क्षमता के टीजी स्टेटर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुमारस्वामी ने स्टेटर के सफल निर्माण एवं डिस्पैच को बीएचईएल की तकनीकी उत्कृष्टता का एक नायाब नमूना बताया।

बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के. सदाशिव मूर्ति ने कहा कि यह सोलर पावर प्लांट, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बीएचईएल का एक महत्वपूर्ण कदम है। हरिद्वार इकाई के कार्यपालक निदेशक रंजन कुमार ने बताया कि इस संयंत्र से प्राप्त बिजली, संस्थान की आंतरिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। कुमारस्वामी ने बीएचईएल कर्मचारियों के साथ भी विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इन अवसरों पर महाप्रबंधकगण, वरिष्ठ अधिकारी, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी

एजेंसी, नई दिल्ली/श्रीनगर/देहरादून/जयपुर

पहाड़ी राज्यों में एकबार फिर बर्फबारी हो रही है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। यहां स्नोफॉल के साथ बारिश का भी अलर्ट है। हिमाचल में 24 घंटे में तापमान 8°C कम हुआ। मनाली का तापमान 12.6°C रहा, इसमें 7°C की कमी आई। वहीं, सोलन में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है। आज 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट है। इधर देहरादून में अधिकतम तापमान 34.1°C रहा, यहां गर्मी से लोग परेशान हैं।

राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में अधिकतम तापमान 39-41°C के बीच रहा। सबसे

◆ राजस्थान में तापमान 40° पार, एमपी में आज से लू का अलर्ट

ज्यादा 39.4 बाड़मेर में रहा। राज्य के 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में आज से हीटवेव का अलर्ट है। नर्मदापुरम में दिन का अधिकतम तापमान 40.2°C और 10 शहरों में तापमान 38°C से ज्यादा रहा। 15 और 16 मार्च को प्रदेश में बारिश की संभावना है।

नेपाल-भारत के बीच बिजली की खरीद और बिक्री की नई दरें लागू होंगी, बनी सहमति

एजेंसी, काठमांडू

भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से एक साल तक नेपाल को बिजली आयात करने और उसकी नई दर लागू करने पर सहमति बनी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार पोखरा में १२ और १३ मार्च को हुई एक बैठक में आगामी एक वर्ष के लिए बिजली खरीद दर निर्धारित की गई। बैठक में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक हितेंद्र देव शाक्य और भारत की ओर से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी के बोर्ड सदस्य विजय कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। वार्ता के दौरान भारत की ओर से बिजली उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए बिजली खरीद दर में 5.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। नेपाल की ओर से भारतीय बिजली बाजार के अध्ययन और उपलब्ध बाजार सूचकांकों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि वर्तमान बाजार दर अपेक्षाकृत

कम है, इसलिए दर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक शाक्य ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद पिछले वर्ष निर्धारित दर में केवल 1.5 प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमति बनी, जो कि पिछले वर्ष की वृद्धि दर के समान है।

उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के लिए 132 केवी प्रसारण लाइन के माध्यम से खरीदी जाने वाली बिजली की दर प्रति यूनिट 8.22 रुपये, 33 केवी स्तर पर प्रति यूनिट 8.91 रुपये तथा 11 केवी स्तर पर प्रति यूनिट 9.55 रुपये तय की गई है। साथ ही बिजली खरीद दर की संरचना के विषय में अगले वर्ष फिर से विस्तृत समीक्षा कर चर्चा करने पर भी सहमति बनी है।

सरकार बोली- पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं, एलपीजी चिंता का विषय

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बीच भारत सरकार ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन अवग-अलग मंत्रालयों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से LPG हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने बताया कि ईरान जंग के कारण देश में गैस बुकिंग की संख्या में लगभग 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की

जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि जंग से पहले हर रोज औसतन 55.7 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी। अभी एक दिन में लगभग 75.7 लाख गैस बुकिंग हो रही है। सरकार ने कहा कि जंग के माहौल के बीच LPG सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। यह लोगों के बीच घबराहट

❑ रोजाना 75.7 लाख सिलेंडर बुक हो रहे, ईरान जंग से पहले 55.7 लाख होते थे

के कारण हो रहा है।

सरकार ने कहा- LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अभी गैस का स्टॉक: पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा- LPG चिंता का विषय है क्योंकि देश का ज्यादातर LPG स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है और वह अभी बंद है। हालांकि, हमारे 25,000 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी पर भी गैस खत्म होने (ड्राई आउट) की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मंत्रालय ने आगे कहा- केंद्र की तरफ से राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन आवंटन किया गया है। राज्यों से अपील की गई है कि व जिलों में केरोसिन बांटने लिए जगह तय करें। वैकल्पिक ईंधन विकल्पों के लिए कोल इंडिया को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि LPG की पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी LPG डीलर पर गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है। 9 मार्च 2026 को जारी नेचुरल गैस ऑर्डर के तहत कई सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। उसी आदेश के अनुसार घरेलू पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) की आपूर्ति बिना किसी कटौती के जारी है।

कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश(पीरियड लीव) को अनिवार्य बनाने की याचिका खारिज़ -समानता,अवसर और व्यावहारिकता के बीच संतुलन का प्रश्न-एक समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» सरकार क्रो व्यापक चर्चा के बाद ऐसी नीति तैयार की जरूरत, जो महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान व उनके रोजगार अवसरों को सुरक्षित रखे

» नियोक्ताओं को हर महीने अतिरिक्त भुगतान वाली छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी तो संभवतःवे महिलाओं क्री नियुक्त करने से बचें- सटीक दृष्टिकोण -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण विश्व राजनीति,सामाजिक नीति और आर्थिक विकास का केंद्रीय विषय बन चुका है। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में यह स्वीकार किया जा चुका है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी,महिलाएं समानअवसरों सम्मान और संसाधनों तक बराबरी से पहुँच प्राप्त करे। भारत भी इसी वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए महिलाओं के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ चला रहा है।भारत सरकार द्वारा संचालित कई कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,प्रधानमंत्रीउज्ज्वला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। इन योजनाओं ने न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है बल्कि समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत किया है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि महिलाएं केवल समाज की आधी आबादी ही नहीं हैं, बल्कि वे मां,पत्नी,बहन,बेटी और परिवार की आधारशिला भी होती हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करना सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि कई बार कुछ ऐसी नीतिगत मांगें भी सामने आती हैं जिनका उद्देश्य भले ही महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य हो,लेकिन उनके सामाजिक और आर्थिक परिणाम जटिल हो सकते हैं ऐसा ही एक मुद्दा हाल ही में सामने आया जब कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने 13 मार्च 2026 को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के प्रावधान को कानूनन अनिवार्य करना महिलाओं के रोजगार अवसरों को प्रभावित कर सकता है।यह निर्णय केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों, समानता और रोजगार के अवसरों के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। साथियों बात अगर हम मासिक धर्म अवकाश की मांगः पृष्ठभूमि और तर्क को समझने की करें तो मासिक धर्म महिलाओं केजीवन का एक स्वाभाविक जैविक चक्र है। हर महीने आने वाला यह शारीरिक परिवर्तन कई महिलाओं के लिए सामान्य होता है,लेकिन कईमहिलाओं को इस दौरान तीव्र दर्द कमजोरी हार्मोनल असंतुलन और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।यही कारण है कि कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से यह मांग उठाई है कि कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को इस दौरान विशेष अवकाश दिया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि भारत में गर्भावस्था और प्रसूति के लिए छुट्टी का प्रावधान तो मौजूद है जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लेकिन मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक तकलीफों को लेकर कोई विशेष कानूनी व्यवस्था नहीं है।याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यदि महिलाओं को हर महीने एक या दो दिन का पीरियड लीव मिल जाए तो इससे उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता दोनों में सुधार होगा। उनका यह भी कहना था कि कुछ राज्य सरकारों और निजी कंपनियों ने स्वेच्छा से ऐसे प्रावधान लागू किए हैं,इसलिए इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। साथियों बात अगर हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क़े दृष्टिकोणक़ो समझने की करें तो व्यावहारिकता बनाम भावनात्मकता, याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे को केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यावहारिक औरआर्थिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर जोर दिया अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी कंपनी या संस्थान द्वारा स्वेच्छा से महिलाओं को पीरियड लीव दिया जाता है तो यह स्वागत योग्य है।लेकिन जब इसे कानून के रूप में अनिवार्य किया जाएगा,तो इसके कई अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि नियोक्ताओं को हर महीने अतिरिक्त भुगतान वाली छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी तो संभव है कि वे महिलाओं को नियुक्त करने से बचें।अदालत की यह टिप्पणी भारतीय श्रम बाजार की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर की गई थी। भारत में अभी भी बड़ी संख्या में निजी कंपनियां लागत और उत्पादकता के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करती हैं। ऐसे में यदि महिला कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अतिरिक्त छुट्टियाँ देनी पड़ें, तो कई नियोक्ता पुरुष कर्मचारियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। साथियों बात अगर हम याचिका खारिज करने के कर्म को समझने की करें तो रोजगार अवसरों पर संभावित प्रभाव, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि महिलाओं को कमजोर बताने वाली मानसिकता सेबचना चाहिए। अदालत के अनुसार यदि कानून यह संदेश देता है कि महिलाएं हर महीने काम करने में सक्षम नहीं हैं, तो इससे कार्यस्थल पर उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है।उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी दो उम्मीदवारों में से एक का चयन कर रही हो एक पुरुष और एक महिला तो नियोक्ता यह सोच सकता है कि महिला कर्मचारी को अतिरिक्त छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी, जिससे उत्पादकता प्रभावित होगी।ऐसी स्थिति में महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह विडंबना होगी कि महिलाओं के हित में बनाई गई नीति ही उनके लिए बाधा बन जाए। साथियों बात अगर हम महिला सशक्तिकरण और समानता की वास्तविक चुनौती को समझने की करें तो महिला सशक्तिकरण केवल सुविधाएँ देने से नहीं बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करने से आता है। यदि कोई नीति महिलाओं को विशेष सुविधा देती है लेकिन उसके परिणामस्वरूप उन्हें रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, तो वह नीति अंततः उनके हितों के विपरीत हो सकती है। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करते हुए उनके रोजगार अवसरों को भी सुरक्षित रखना है मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं बल्कि सामाजिकसंवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है। कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए अधिक संवेदनशील और सहयोगी वातावरण बनाना चाहिए।कई कंपनियां पहले से ही लचीले कार्य समय, वर्क फ्रॉम होम और स्वास्थ्य अवकाश जैसी सुविधाएँ दे रही हैं। यदि इन व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए तो महिलाओं को बिना किसी अतिरिक्त कानूनी बोझ के भी सटीक रूप से राहत मिल सकती है। साथियों बात अगर हम अदालत की सामाजिक चेतावनी को समझने की करें तोसुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मासिक धर्म को किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तरह प्रस्तुत करना भी सही नहीं है। महिलाओं की जैविक प्रक्रिया को सम्मान और सामान्यता के साथ देखा जाना चाहिए।अदालत के अनुसार यदि पीरियड लीव को अनिवार्य कानून बना दिया गया, तो इससे समाज में यह धारणा बन सकती है कि महिलाएं नियमित रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।इस प्रकार अदालत ने महिला सशक्तिकरण के उस सिद्धांत पर जोर दिया जिसमें महिलाओं को कमजोर या निर्भर नहीं बल्कि सक्षम और बराबरी के भागीदार के रूप में देखा जाता है। नियोक्ताओं की चिंता और आर्थिक वास्तविकतासुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची ने भी यह टिप्पणी की कि याचिका का विचार अच्छा है, लेकिन नियोक्ताओं की स्थिति को भी समझना जरूरी है। यदि हर महिला कर्मचारी को महीने में दो दिन अतिरिक्त पेड लीव देनी पड़े, तो इसका आर्थिक बोझ कंपनियों पर पड़ेगा। खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह बोझ अधिक हो सकता है।भारत जैसे विकासशील देश में जहां रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती है, वहां किसी भी नई नीति को लागू करते समय उसके आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना आवश्यक है। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को नीति बनाने का सुझाव को समझने की करें तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उसने इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष अपना ज्ञापन दे चुके हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि सरकार इस विषय पर सभी हितधारकों महिला संगठनों, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से चर्चा कर एक संतुलित नीति बनाने पर विचार कर सकती है।इसका अर्थ यह है कि अदालत ने इस मुद्दे को नकारा नहीं बल्कि इसे नीति निर्माण के दायरे में भेज दिया। साथियों बात अगर हम इस पूरे मामले को वैश्विक परिप्रेक्ष्य मैं समझने की करें व दुनिया में पीरियड लीव की व्यवस्था को देखें तो दुनिया के कुछ देशों में पीरियड लीव का प्रावधान मौजूद है। उदाहरण के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी लेने का अधिकार दिया गया है।हाल ही में स्पेन ने भी महिलाओं को पीरियड लीव देने का कानून लागू किया। लेकिन कई देशों में यह व्यवस्था विवादित भी रही है क्योंकि इससे महिलाओं की भर्ती में भेदभाव की आशंका बढ़ सकती है।यही कारण है कि कई विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि पीरियड लीव को अनिवार्य कानून बनाने के बजाय कंपनियों को लचीली नीतियाँ अपनाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि संतुलित नीति ही समाधान, मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा महिलाओं के स्वास्थ्य समानता और रोजगार के अवसरों से जुड़ा एक जटिल विषय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह संकेत देता है कि किसी भी सामाजिक नीति को लागू करने से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।महिलाओं को कमजोर या असहाय बताने के बजाय उन्हें सक्षम और स्वतंत्र नागरिक के रूप में देखना ही वास्तविक सशक्तिकरण है।भविष्य में संभव है कि सरकार व्यापक चर्चा के बाद ऐसी नीति तैयार करे जो महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और उनके रोजगार अवसरों को भी सुरक्षित रखे।अंततः महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य केवल विशेष सुविधाएँ देना नहीं बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ महिलाएं बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकें।और यही वह संतुलन है जिसे बनाए रखना किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स का गिरनाः क्या अर्थतंत्र में महासंकट के संकेत?

लेखक- सौरभ वार्ष्णेय

वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब भी ऊर्जा संकट गहराता है, उसका सीधा असर वित्तीय बाजारों और आम लोगों की जेब पर दिखाई देता है। हाल के दिनों में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी तथा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक गिरावट की ओर गया है। यह गिरावट केवल बाजार की सामान्य हलचल नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़े संभावित बड़े संकट का संकेत भी हो सकती है। वहीं जब मैं इस लेख को लिख रहा हूं तो सेंसेक्स और निफ्टी काफी हद तक गिर चुका है। ऐसे में सरकार के कहने के बावजूद जनमानस इस युद्ध के बीच ऊर्जा का भंडार भरकर रखना चाहता है, यह युद्ध क्या पटकथा लिखेगा कोई नहीं जानता क्योंकि रुस-युक्रेन युद्ध भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ। भारत जैसे देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। जब वैश्विक स्तर पर तेल-गैस की कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति बाधित होती है, तो उसका असर सीधे महंगाई, उत्पादन लागत और व्यापार संतुलन पर पड़ता है। उद्योगों की लागत बढ़ती है, परिवहन महंगा होता है और अंततः इसका बोझ आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। निवेशकों को भी यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है। शेयर बाजार का गिरना इसी चिंता का प्रतिबिंब है। निवेशक भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए बाजार से पैसा निकालने लगते हैं। विदेशी निवेशक भी जोखिम से बचने के लिए उभरते बाजारों से पूंजी निकालते हैं, जिससे बाजार में गिरावट और तेज हो जाती है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास की गति पर पड़ सकता है। ऊर्जा संकट का दूसरा पहलू राजकोषीय दबाव भी है। सरकार को महंगाई नियंत्रित करने के लिए करों में कटौती, सब्सिडी या अन्य राहत उपाय देने पड़ सकते हैं। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। साथ ही यदि आयात बिल बढ़ता है तो चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन जाता है। हालांकि यह भी सच है कि शेयर बाजार हमेशा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति का सटीक दर्पण नहीं होता। कई बार वैश्विक परिस्थितियों, भू-राजनीतिक तनाव या निवेशकों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से भी बाजार अचानक गिर सकता है। इसलिए सेंसेक्स की गिरावट को तुरंत महा संकट मान लेना भी उचित नहीं होगा। लेकिन इसे एक चेतावनी संकेत जरूर माना जाना चाहिए। ऐसे समय में सरकार और नीति-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की है। देश को तेल-गैस के आयात पर निर्भरता कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और रणनीतिक भंडार बढ़ाने जैसी नीतियों पर तेजी से काम करना होगा। साथ ही आर्थिक सुधारों और निवेश को बढ़ावा देकर बाजार का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है। अंततः कहा जा सकता है कि तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स की गिरावट केवल बाजार की घटना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों की याद दिलाती है। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो यह संकट अवसर में भी बदल सकता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इसके गंभीर आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं।

निवेशक दोहरी दुविधा में-वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के बीच आज निवेशक एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बाजार में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय तनाव और महंगाई के दबाव ने निवेशकों को दोहरी दुविधा में डाल दिया है। एक ओर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित निवेश विकल्प भी अपेक्षित रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे माहौल में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि निवेशक अपने धन को कहाँ और कैसे सुरक्षित रखें। हाल के समय में वैश्विक स्तर पर कई घटनाएँ आर्थिक बाजारों को प्रभावित कर रही हैं। तेल-गैस की कीमतों में अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों में बदलाव का असर भारत सहित दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। जब भी वैश्विक स्तर पर संकट गहराता है, निवेशक जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं।

युद्ध काल में ऊर्जा संकट भारत की संतुलित रणनीति

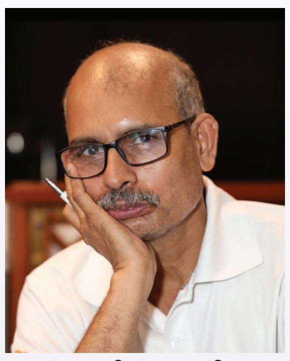

लेखक : बिनोद कुमार सिंह

वैश्विक परिपेक्ष में आज विश्व ऐसे दौर से गुजर रही है।जहाँ युद्ध,ऊर्जा संकट,आपूर्ति श्रृंखला की अस्थिरता और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर–मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल प्रशासनिक जानकारी साझा करने का मंच नहीं थी,बल्कि यह उस व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि का संकेत भी थी।जिसके माध्यम से भारत बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट कर रहा है।विदेश,पेट्रोलियम, वाणिज्य और ऊर्जा से जुड़े मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने वैश्विक युद्ध परिस्थितियों,ऊर्जा बाजार की अनिश्चितताओं,अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और भारत की दीर्घकालिक रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी।यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय में वैश्विक राजनीति का केंद्र केवल सैन्य शक्ति नहीं रहा,बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला,प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय कूटनीति भी उतने ही महत्वपूर्ण कारक बन चुके हैं। आज दुनिया जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है,युद्ध की बढ़ती विभीषिका।विशेष रूप से रूस - यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है।फरवरी 2022 में शुरू हुआ यह संघर्ष अब केवल दो देशों के बीच सीमित युद्ध नहीं रह गया,बल्कि उसने ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति और वैश्विक व्यापार मार्गों को प्रभावित किया है। यूरोप में गैस संकट पैदा हुआ, अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया और कई देशों की मुद्रास्फीति दरें तेजी से बढ़ीं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारत पर भी इन परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा भी विदेशों से आती है।ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की अस्थिरता का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था,परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को अपनी राष्ट्रीय नीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित किया है।भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू विविध स्रोतों से आयात सुनिश्चित करना है।पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तेल आयात के अपने स्रोतों का विस्तार किया है और विभिन्न देशों के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है।इस संदर्भ में रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की खरीद ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2021 में जहाँ भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बहुत कम थी,वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर लगभग 35 प्रतिशत के आसपास पहुँच गई। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार की ऊँची कीमतों से काफी राहत मिली। इसी प्रकार पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी भारत के ऊर्जा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।सऊदी अरब,संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों के साथ दीर्घकालिक तेल और गैस आपूर्ति समझौते भारत की ऊर्जा नीति की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और भारत की गैस आधारित ऊर्जा संरचना में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।सौर ऊर्जा,पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है और भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है।विदेश नीति के स्तर पर भारत ने जिस संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया है, वह वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में विशेष महत्व रखता है।रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने के बजाय संवाद और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भारत ने बार-बार यह कहा कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता और सभी पक्षों को बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशना चाहिए।यह संतुलित नीति भारत को पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की क्षमता देती है।एक ओर भारत के रणनीतिक संबंध अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ लगातार मजबूत हो रहे हैं,वहीं दूसरी ओर रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग भी जारी है।यही बहु-आयामी कूटनीति आज की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है।वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है।विशेष रूप से BRICS समूह में भारत की सक्रियता इस दिशा में महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स - जिसमें ब्राजील, रूस, भारत,चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं -आज वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करने वाला प्रमुख मंच बन चुका है। इस समूह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अधिक संतुलित और समावेशी बनाना है।ब्रिक्स देशों की कुल आबादी विश्व की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।हाल के वर्षों में इस समूह ने नई विकास बैंक के माध्यम से विकासशील देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल भी की है।भारत इस मंच का उपयोग वैश्विक दक्षिण की विकास आवश्यकताओं को अंतरराष्ट्रीय नीति विमर्श के केंद्र में लाने के लिए कर रहा है। अंतर–मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत की राष्ट्रीय नीति केवल तत्काल संकटों से निपटने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार,रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता बढ़ाने, गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश जैसे कदम इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भी मजबूत किया है।देश में विशाखा पत्तनम,मंगलुरु और पाडुर जैसे स्थानों पर भूमिगत तेल भंडारण सुविधाएँ विकसित की गई हैं,जो आपातकालीन परिस्थितियों में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज जब दुनिया अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है,तब भारत की नीति का मूल आधार संतुलन, व्यावहारिकता और दीर्घकालिक दृष्टि है।युद्ध की विभीषिका,ऊर्जा संकट और आर्थिक अस्थिरता के बीच भारत ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए भी वैश्विक सहयोग और शांति को प्राथमिकता दी जा सकती है। अंतर–मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश भी यही था कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि वह सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर वैश्विक कूटनीति तक,भारत एक ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है जिसमें राष्ट्रीय विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग दोनों के लिए समान स्थान है।यह वही दृष्टि है जो आने वाले वर्षों में भारत को केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं,बल्कि एक स्थिर,विश्वसनीय और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है।

इच्छा मृत्यु केवल कानून ही नहीं, मानवीय गरिमा का प्रश्न

लेखक- ललित गर्ग

भारतीय समाज में यह गहरी धारणा रही है कि परिवार के किसी सदस्य की सेवा तब तक की जाए, जब तक उसके प्राण स्वाभाविक रूप से समाप्त न हो जाएं। जीवन की रक्षा और उसकी देखभाल को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में रोगी की सेवा केवल चिकित्सा का विषय नहीं होती, बल्कि भावनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से भी जुड़ी होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि प्रियजन की मृत्यु के बाद भी उसे लंबे समय तक जीवन लौटने की आशा में संभालकर रखा जाता रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, जहां से सामान्य जीवन में लौटने की कोई संभावना न हो और उसका अस्तित्व केवल कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों पर निर्भर रह जाए, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल जैविक अस्तित्व को बनाए रखना ही जीवन की रक्षा है? या फिर जीवन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पीड़ा से मुक्ति देने का अधिकार भी स्वीकार किया जाना चाहिए? इसी जटिल और संवेदनशील प्रश्न के केंद्र में 11 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया वह निर्णय है, जिसमें गाज़ियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई। लगभग तेरह वर्षों से कोमा में जीवन बिताने वाले इस युवक के मामले में अदालत का यह निर्णय केवल एक कानूनी आदेश भर नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन खोजने का एक गंभीर एवं संवेदनशील प्रयास भी है। दरअसल, हरीश राणा का मामला हमें यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि इच्छामृत्यु का प्रश्न केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि एक गहरी मानवीय कहानी भी है। यह एक ऐसे युवा की कहानी है, जिसका जीवन एक दुर्घटना के बाद अचानक बदल गया और जो तेरह वर्षों तक एक मौन जीवन-मृत्यु संघर्ष में जीता रहा। उस संघर्ष में शब्द नहीं थे, संवाद नहीं था, केवल एक स्थिर और असहाय जैविक अस्तित्व था। ऐसे में परिवार, चिकित्सकों और समाज के सामने यह कठिन दुविधा खड़ी हो जाती है कि जीवन को किस सीमा तक कृत्रिम रूप से बनाए रखा जाए। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समय के साथ न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए यह स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार केवल सांस लेने या जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी है। इसी संवैधानिक दृष्टिकोण ने आगे चलकर यह प्रश्न उठाया कि यदि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, तो क्या उसे गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी नहीं होना चाहिए? भारत में इच्छामृत्यु से जुड़ा न्यायिक विमर्श धीरे-धीरे विकसित हुआ है। वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। यह मामला एक ऐसी नर्स का था, जो दशकों तक कोमा की स्थिति में रही। उस निर्णय ने इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। इसके बाद वर्ष 2018 में कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को संवैधानिक मान्यता देते हुए 'लिविंग विल' की अवधारणा को स्वीकार किया। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही यह लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है कि यदि वह असाध्य स्थिति में पहुंच जाए तो उसे कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों पर निर्भर न रखा जाए। हरीश राणा के मामले में चिकित्सा विशेषज्ञों के बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि निरंतर उपचार का कोई चिकित्सीय उद्देश्य शेष नहीं रह गया था। चिकित्सा केवल जैविक अस्तित्व को लंबा खींचने का माध्यम बन गई थी। ऐसे में अदालत की स्वीकृति इस कठिन सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन की गरिमा केवल जीने में ही नहीं, बल्कि मृत्यु में भी बनी रहनी चाहिए। फिर भी इच्छामृत्यु का प्रश्न अत्यंत जटिल और विवादास्पद रहा है। दुनिया के अनेक देशों में इस विषय पर गंभीर नैतिक और कानूनी बहस चलती रही है। कई देशों ने इसे सीमित परिस्थितियों में कानूनी मान्यता दी है, जबकि कई अन्य देशों में इसके दुरुपयोग की आशंका के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में भी यह विषय संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि यहां पारिवारिक संबंधों, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक भावनाओं की भूमिका अत्यंत गहरी है। इसी संदर्भ में जैन धर्म में प्रचलित संथारा या सल्लेखना की परंपरा भी कई बार चर्चा में आती रही है। जैन दर्शन में इसे मृत्यु का महोत्सव कहा गया है। संथारा का अर्थ है-जीवन के अंतिम चरण में धीरे-धीरे आहार और शरीर की आसक्तियों का त्याग करते हुए शांति एवं समाधिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना।

आरोण्यक घोष बने राष्ट्रीय रैपिड शतरंज चैंपियन

रांची (एजेंसी)। शतरंज के फटाफट फॉर्मेट रैपिड और ब्लिट्ज की राष्ट्रीय चैंपियनशिप इस समय रांची की बिरला विश्वविद्यालय में खेले जा रहे है और पहले दो के 11 राउंड के रैपिड मुक़ाबले के बाद देश को नया रैपिड चैंपियन रेलवे के अरोण्यक घोष के तौर पर मिला है . उन्होंने सर्वाधिक 9.5 अंक बनाते हुए खिताब अपने नाम किया ,2541 रेटिंग का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 8 जीत और 3 ड्रा के साथ अपराजित रहते हुए खिताब अपने नाम किया इस दौरान सातवे से नौवे राउंड के दौरान प्रतियोगिता के शीर्ष तीन वरीय खिलाड़ी अभिमन्यु पौराणिक , मुरली कार्तिकेयन और मित्रभा गुहा पर उनकी जीत नें उनके लिए खिताब की राह आसान बना दी और अंतिम दोनों राउंड उन्होंने सम्हलकर खेलते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। 9 अंक बनाकर टाईब्रेक के आधार पर तमिलनाडु के मुरली कार्तिकेयन दूसरे और हरि माधवन तीसरे स्थान पर रहे । देश भर से कुल 11 ग्रैंड मास्टर्स समेत कुल 219 खिलाड़ियों नें इसमें प्रतिभागिता की जिसमें कुल 55 टाइटल खिलाड़ी थे ।

युवाराज से पावर हिटिंग सीख रहे ऋषभ पंत

आईपीएल से पहले स्टांस बदला, पिछले सीजन में 269 रन ही बना सके थे

मुंबई (एजेंसी)। आईपीएल के पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत अब युवराज सिंह से पावर हिटिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पंत मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में युवराज की निगरानी में बड़े-बड़े शॉर्ट खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो में युवराज सिंह उनकी तकनीक को ध्यान से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हें बल्लेबाजी से जुड़े सुझाव भी देते नजर आ रहे हैं। पंत के लिए आईपीएल का पिछला सीजन काफी खराब रहा था। वे एक शतकीय पारी के बावजूद महज 269 रन ही बना सके थे।

लेफ्टी बॉलर्स के खिलाफ स्टांस बदला- इस ट्रेनिंग सेशन में पंत ने ओपन स्टांस लिया यानी कि वे बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ थोड़े खुले पैरों के साथ बैटिंग करते दिखे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव से उन्हें ऑफ-साइड में बड़े शॉट खेलने और बेहतर एंगल कवर करने में मदद मिलेगी। पंत चोट से वापसी कर रहे हैं। वे 11 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से ठीक पहले चोटिल हो गए थे। ट्रेनिंग सेशन के दौरान थ्रोडाउनर की बॉल पंत की दाहिनी पसलियों पर लगी थी। वे इस सीरीज से बाहर हो गए थे। उन्होंने पिछला इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में 22 से 26 नवंबर 2025 को खेला था।

युवाओं के मेंटर बन चुके हैं युवराज

युवराज सिंह पिछले कुछ वर्षों में युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मेंटर साबित हुए हैं। उन्होंने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है।

● कुलदीप यादव की शादी में रिंकू सिंह-युजवेंद्र चहल मसूरी पहुंचे

बोले- भाई की शादी, फुल डांस होगा

शाम को संगीत और कॉकटेल पार्टी आयोजित

मसूरी (एजेंसी)। कुलदीप यादव की शादी को लेकर मसूरी में समारोह शुरू हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से हल्दी की रस्म शुरू हुई, जो दोपहर करीब दो बजे के बाद खत्म हुई। इसके बाद मेहमानों ने खास दावत का आनंद लिया, जिसमें एक थाली की कीमत 20 हजार रुपए से ज्यादा है।

हल्दी के बाद समारोह में डांस और मस्ती का दौर शुरू हो गया। इससे पहले ही क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां मसूरी पहुंच चुकी थीं। इसके अलावा रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, कैलाश खेर और बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर भी समारोह में शामिल होने के लिए मसूरी पहुंचे हैं।

क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ नजर आए। वहीं, युजवेंद्र चहल ने कहा कि भाई की शादी है, फुल डांस होगा। भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप भी समारोह में शामिल होने के लिए मसूरी पहुंच चुके हैं। वहीं, शाम तक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को शादी समारोह में सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के भी शामिल होने की उम्मीद है।

बचपन की दोस्त से शादी कर रहे कुलदीप- मसूरी में होने वाली इस शादी को लेकर होटल और आसपास के इलाकों में खास तैयारियां की गई हैं। अभी होटल में कुलदीप यादव के दोस्त मस्ती और डांस कर रहे हैं। कुलदीप अपनी मंगेतर और बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ 14 मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। यह रॉयल वेडिंग उत्तराखंड के मसूरी स्थित आलीशान आईटीसी सेवॉय होटल में हो रही है। शादी के कार्यक्रम 12 मार्च से शुरू हुए थे, जो 14 मार्च तक चलेंगे। डिजिटल इन्विटेशन कार्ड में मेहंदी, हल्दी, संगीत, कॉकटेल और शादी के मुख्य कार्यक्रम की पूरी जानकारी साझा की गई है। कुलदीप 12 मार्च को देहरादून पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद वह कार से मसूरी पहुंचे। होटल के एंट्री गेट पर कुलदीप यादव नाचते और जश्न मनाते हुए नजर आए।

हल्दी रस्म हुई
संगीत और कॉकटेल

13 मार्च को सुबह 11 बजे होटल के बीयर गार्डन में हल्दी की रस्म हुई। इसके बाद शाम 6 बजे सेंट्रल लॉन में ग्रैंड संगीत और कॉकटेल पार्टी आयोजित थी।

● **कुलवंश के नाम से ट्रेंड करेगी शादी**- डिजिटल इन्विटेशन कार्ड की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से की गई है। कार्ड को रॉयल और मॉडर्न लुक दिया गया है, जिसमें कुलदीप यादव और वंशिका सिंह के एनिमेटेड अवतार भी नजर आते हैं। कपल ने अपनी शादी के लिए कुलवंश चुना है। यह हैशटैग कुलदीप के नाम के 'कुल' और वंशिका के नाम के 'वंश' को मिलाकर बनाया गया है। माना जा रहा है कि शादी से जुड़े फोटो और वीडियो इसी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किए जाएंगे।

ज्वेरेव पहली बार इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में

● एटीपी मास्टर्स के सभी 9 इवेंट्स में आखिरी-4 खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बने

कैलिफोर्निया (एजेंसी)। ज्वेरेव ने कैलिफोर्निया में खेले जा रहे इंडियन वेल्स के क्वार्टरफाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स को 6-2, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई।

जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने गुरुवार को इंडियन वेल्स मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में आर्थर फिल्स को 6-2, 6-3 से हराया।

इस जीत के साथ ज्वेरेव एटीपी मास्टर्स-1000 के सभी नौ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेलने वाले सिर्फ पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मरे यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

बिग फोर के क्लब में शामिल

इस उपलब्धि के साथ ज्वेरेव बिग फोर यानी रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे के चुनिंदा खिलाड़ी क्लब में शामिल हो गए हैं। ज्वेरेव ने कहा,इतिहास में ऐसा करने वाले सिर्फ पांच खिलाड़ियों में शामिल होना मेरे लिए बहुत खास है। यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर मुझे गर्व है।

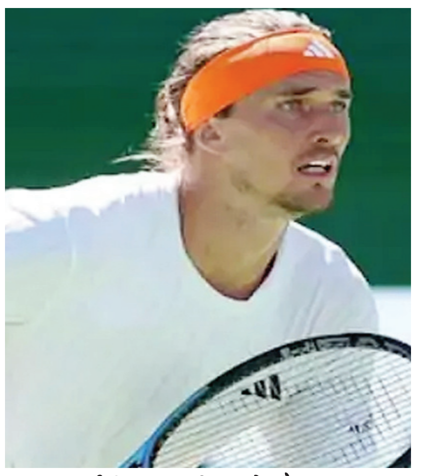

मास्टर्स खिताब जीत चुके हैं- ज्वेरेव अब तक नौ में से पांच मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। हालांकि, वह अभी तक कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीत पाए हैं, जबकि तीन बार फाइनल तक पहुंच चुके हैं।

सेमीफाइनल में सिनर से मुकाबला- सेमीफाइनल में ज्वेरेव का मुकाबला इटली के वर्ल्ड नंबर-2 जेनिक सिनर से होगा। सिनर के खिलाफ ज्वेरेव का रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा है और वह लगातार पांच मैच हार चुके हैं।

सिनर ने क्वार्टरफाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी लर्नर टिएन को सिर्फ 66 मिनट में 6-1, 6-2 से हराया। सिनर अभी तक इंडियन वेल्स का खिताब नहीं जीत पाए हैं और इस साल अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश में हैं। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल और कतर ओपन के क्वार्टरफाइनल में हारकर बाहर हो गए थे।

क्या है एटीपी मास्टर्स 1000 का 'सेट'

टेनिस में ग्रैंड स्लैम के बाद मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। एक साल में कुल 9 ऐसे टूर्नामेंट होते हैं-इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे कार्लो, मैड्रिड, रोम, कनाडा, सिनसिनाटी, शंघाई और पेरिस। इन सभी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचना किसी खिलाड़ी की निरंतरता और उच्च स्तर के प्रदर्शन को दर्शाता है। ज्वेरेव ने इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना यह 'सेट' पूरा कर लिया है।

अल्काराज लगातार पांचवीं बार इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे

इंडियन वेल्स (एजेंसी)। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपनी जीत का सिलसिला 16 मैचों तक बढ़ाया और गुरुवार को बीएनपी परीबा ओपन में लगातार पांचवें इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। टॉप सीड खिलाड़ी ने कैमरन नॉरी के खिलाफ 6-3, 6-4 से जीत हासिल की, जिससे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाड़ी से बदला ले लिया, जिसने उन्हें पिछले नवंबर में पेरिस में हराया था।

अल्काराज ने कोर्ट पर अपने इंटरव्यू में नॉरी के बारे में कहा, मुझे उनके स्टाइल से बहुत दिक्कत होती है। हर बार जब मैं उनके खिलाफ खेलता हूं तो यह मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल होता है। उनके स्टाइल, उनके (हैवी) टॉपस्पिन फोरहैंड, सुपर हाई के साथ यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। और फिर बैकहैंड, बहुत फ्लैट और बहुत लो। कभी-कभी उनके खिलाफ खेलना मुश्किल होता है। मुझे सही शॉट मिल रहा है। मैंने अच्छा खेला। मैंने सॉलिड खेला। जब भी हो सका, मैंने एग्रेसिव खेला। मैं इस लेवल पर खेलकर खुश हूं।

अल्काराज और नॉरी ने पूरे मैच में मोमेंटम बदला, लेकिन स्पेन के खिलाड़ी ने ज़्यादातर अपना पलड़ा भारी रखा। पहला सेट आखिरी चार गेम में तीन बार सर्व ब्रेक के साथ खत्म हुआ। इसके बाद नॉरी ने दूसरे सेट में 2-0 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अल्काराज ने लगातार चार गेम जीतकर जवाब दिया। 22 साल के खिलाड़ी ने 10 ब्रेक के मौके बनाए, जिनमें से चार को भुनाया। तेज बेसलाइन हिटिंग, हल्के ड्रॉप शॉट और शानदार नेट प्ले का मिक्स दिखाते हुए, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने एक घंटे 33 मिनट में जीत हासिल की।

59 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया टाटा एलेक्सी का शेयर, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 59 प्रतिशत से ज्यादा टूट गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयर 17 अगस्त 2022 को 10,760.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 मार्च 2026 को 4327.50 रुपये पर बंद हुए हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। टाटा एलेक्सी के शेयर पिछले 6 महीने में 24 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 17 पर्सेंट टूट गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयर गुरुवार 12 मार्च को भी गिरावट के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4327.50 रुपये पर बंद हुए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयरों में अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 59 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। टाटा एलेक्सी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 59 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयर 17 अगस्त 2022 को 10,760.40 रुपये के लेवल पर थे। कंपनी के शेयर 12 मार्च 2026 को 4327.50 रुपये पर बंद हुए हैं।

न्यू लेबर कोड में ईपीएफओ के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, सरकार ने संसद में दी यह जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नई लेबर कोड व्यवस्था लागू होने के बाद भी फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूदा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नई लेबर कोड व्यवस्था लागू होने के बाद भी फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूदा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी मौजूदा स्कीम कुछ समय तक पहले की तरह ही जारी रहेगी। दरअसल, राज्यसभा सांसद सन्दोश कुमार पी ने सरकार से पूछा था कि क्या जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और क्या नई लेबर कोड के तहत स्कीम में कोई बदलाव होगा। इस पर सरकार ने बताया कि ईपीएफओ पर ब्याज दर तय करने का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पहले से तय है और उसी के अनुसार

यह निर्णय लिया जाता है। सरकार के अनुसार, ईपीएफ जमा पर ब्याज दर तय करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार करती है, लेकिन यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड से सलाह लेने के बाद लिया जाता है। इस बोर्ड में सरकार, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ब्याज दर तय करते समय यह भी देखा जाता है कि के निवेश से होने वाली कमाई और फंड की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे और ब्याज खाते में किसी तरह की कमी या ओवरड्रॉ न हो। नई श्रम सुधार व्यवस्था के तहत लागू होने वाला सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 भी सिस्टम की मूल संरचना को बरकरार रखता है। सरकार ने बताया कि जब यह कोड लागू होगा, तब भी मौजूदा स्कीम एक साल तक या तब तक जारी रहेगी जब तक कि वह नए कानून से टकराव में नहीं आती। यानी शुरुआत में कर्मचारियों को से जुड़े नियमों में अचानक कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और नई व्यवस्था धीरे-धीरे लागू की जाएगी। दरअसल, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 देश के चार बड़े लेबर कोड में से एक है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक साथ लाकर व्यवस्था को आसान बनाना है। इस कोड के तहत कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 जैसे कई पुराने कानूनों को एक ढांचे में लाया गया है। नई व्यवस्था का एक बड़ा मकसद सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना भी है।

● सीधा और निर्बाध प्रसंस्करण (एसटीपी) तंत्र शुरू करने का सुझाव दिया

सेबी का निवेशक की मृत्यु के बाद वारिसों को सिक्योरिटीज के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। सेबी के एडवाइजरी के अनुसार नियामक ने सरलीकृत दस्तावेजीकरण के लिए मौद्रिक सीमा में संशोधन करने और छोटे दावों के लिए सीधा और निर्बाध प्रसंस्करण (एसटीपी) तंत्र शुरू करने का सुझाव दिया है ताकि कागजी कार्रवाई कम हो सके और दावों के निपटान में तेजी आए। बाजार नियामक सेबी ने निवेशक की मृत्यु के बाद वारिसों को सिक्योरिटीज के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव किया। इस पहल से नॉमिनी व्यक्ति और कानूनी वारिस वित्तीय संपत्तियों पर आसानी से क्लेम कर सकेंगे। सेबी के एडवाइजरी के अनुसार नियामक ने सरलीकृत दस्तावेजीकरण के लिए मौद्रिक सीमा में संशोधन करने और छोटे दावों के

लिए सीधा और निर्बाध प्रसंस्करण (एसटीपी) तंत्र शुरू करने का सुझाव दिया है ताकि कागजी कार्रवाई कम हो सके और दावों के निपटान में तेजी आए। सेबी ने कहा कि सरलीकृत दस्तावेजीकरण के लिए मौजूदा सीमाएं बहुत पहले तय की गई थीं और सिक्योरिटीज की भारी वृद्धि और संपत्तियों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए मौजूदा सीमाओं की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। प्रस्तावित ढांचे के तहत एक सत्यापन योग्य मृत्यु प्रमाण पत्र में मूल प्रमाण पत्र, नामांकित व्यक्ति द्वारा सत्यापित प्रति, नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति या क्यूआर कोड वाला प्रमाण पत्र शामिल हो सकता है। कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तहसीलदार के पद से नीचे के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी नहीं होना चाहिए। सेबी ने मौद्रिक सीमा में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। एसटीपी के तहत बहुत छोटे क्लेम के लिए लिमिट फिजिकल सिक्योरिटीज के लिए 10,000 रुपये और डीमैट सिक्योरिटीज के लिए 30,000 रुपये होगी। सरलीकृत दस्तावेजीकरण की सीमा फिजिकल होल्डिंग के लिए बढ़ाकर 10 लाख रुपये और डीमैट होल्डिंग के लिए 30 लाख रुपये की जाएगी। जहां नामांकन मौजूद है, वहां प्रक्रिया आसान होगी।

आईपीओ के इश्यू प्राइस पर चली कैंची, क्लोजिंग डेट में बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्लोबल टेंशन के कारण शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। इस माहौल में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का मार्केट भी ठंडा पड़ा है। ऐसे में कंपनियां या तो आईपीओ लॉन्च करने की योजना को आगे बढ़ा रही हैं या फिर अधिक आकर्षित बना रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक दिलचस्पी दिखा सकें। ऐसा ही एक आईपीओ एचआर और टोल प्लाजा प्रबंधन सेवाएं देने वाली कंपनी इनोविजन लिमिटेड का है। कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की अंतिम तारीख 17 मार्च तक बढ़ा दी है। पिछले कार्यक्रम के अनुसार आईपीओ 10 मार्च को खुलकर 12 मार्च को बंद होने वाला था। निवेशकों की ओर से सुस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद कंपनी ने इश्यू के लिए कीमत के दायरे में भी कटौती की है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने अब इश्यू प्राइस को घटाकर 494-519 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले 521-548 रुपये प्रति शेयर था। बता दें कि बोली के लिए कीमत का नया दायरा 13 मार्च से प्रभावी होगा। इश्यू के पहले तीन दिन के दौरान निवेशकों की भागीदारी काफी कम रही।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आंकड़ों के मुताबिक, तीसरे दिन तक आईपीओ को कुल मिलाकर केवल 32 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला था। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व हिस्सा 99 प्रतिशत भरा जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 36 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। केवल 28 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला।

एक्सईडी आईपीओ ने बदली तारीख

इससे पहले, वरिष्ठ पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कंपनी एक्सईडी एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ने अपने 1.2 करोड़ डॉलर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए पहले तय की गई छह मार्च की तारीख से बदलकर 16 मार्च कर दिया है। अब कंपनी का 10 से 10.5 डॉलर प्रति शेयर के इश्यू प्राइस वाला यह आईपीओ 16 मार्च को खुलकर 24 मार्च को बंद होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)